राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

मूल्य: ₹15/-

RNI No. BIHHIN/2007/22741

उभरता बिहार

सच्चाई, ऊर्जा, सकारात्मक विचार

वर्ष : 14, अंक : 05-06, नवंबर-दिसंबर 2021 (संयुक्तांक)

www.ubhartabihar.com | Email : ubhartabihar@gmail.com

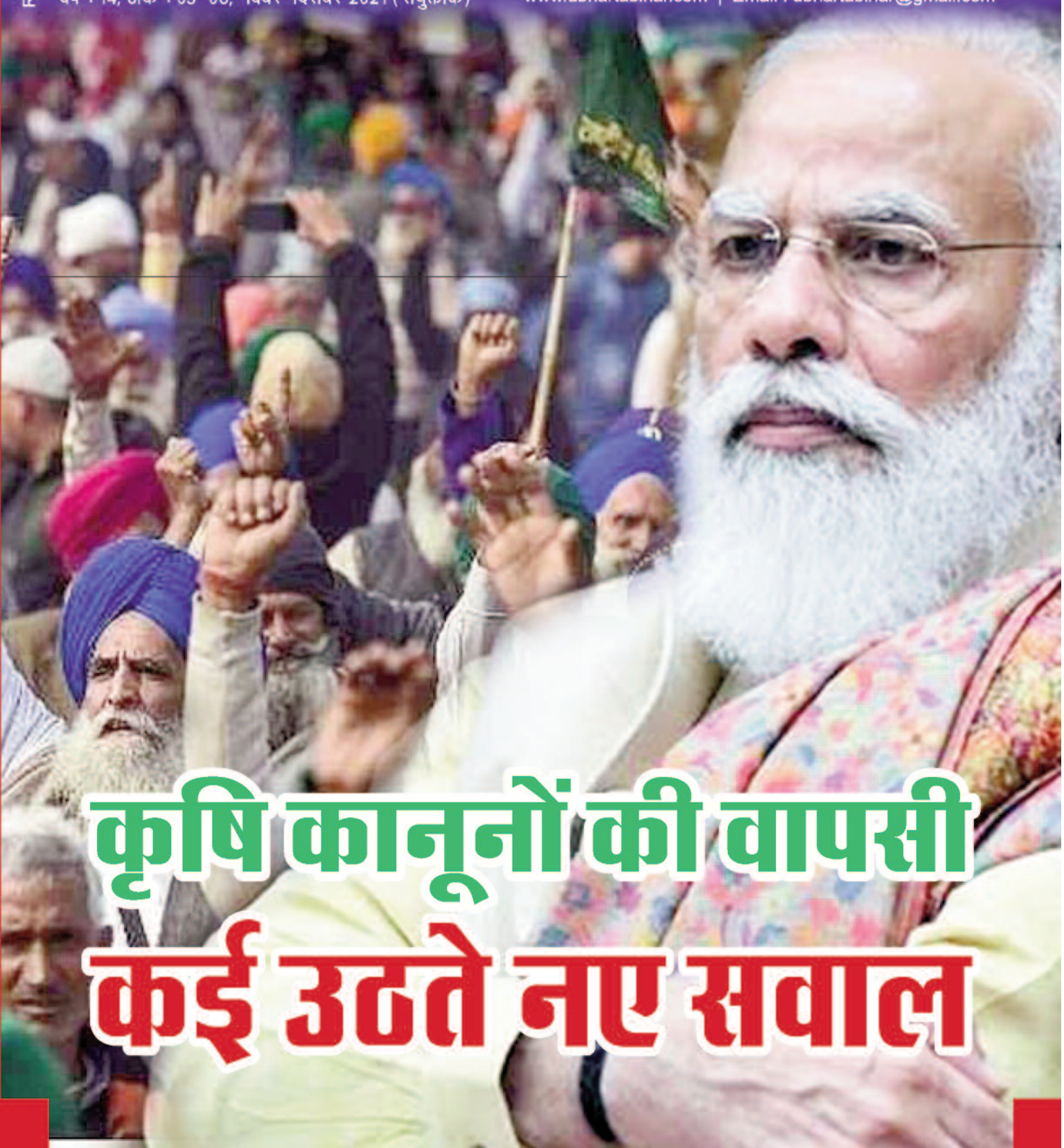

कृषि कानूनों की वापसी कई उठते नए सवाल

श्री राजीव रंजन एवं श्रीमती पल्लवी रंजन की सुपुत्री एवं श्रीमती वीणा कुमारी जायसवाल एवं श्री उपेंद्र प्रसाद की पोती

सुश्री पूर्णिमा
संग
श्रीयुक्त चि० निशांत

श्रीमती सुनीता कुमारी और श्री राकेश कुमार के पुत्र के परिणय सूत्र में बंधने पर
अनंत मंगलकामनाओं के साथ वर-वधू को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई

उभरता बिहार

वर्ष : 14, अंक : 5-6, नवंबर-दिसंबर (संयुक्तांक) 2021

RNI No. BIHHIN/2007/22741

संपादक

राजीव रंजन

छायाकार

विनोद राज

विधि सलाहकार

उपेन्द्र प्रसाद

चंद्र नारायण जायसवाल

साज-सज्जा

मयंक शर्मा

प्रशासनिक कार्यालय

सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर

कंकड़बाग, पटना - 800020

फोन : 7004721818

Email : ubhartabihar@gmail.com

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक राजीव रंजन द्वारा कृत्या पब्लिकेशन, लंगरटोली, बिहार से मुद्रित एवं सी-49 हाऊसिंग कॉलोनी, लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना - 800020 से प्रकाशित।

संपादक: राजीव रंजन

सभी कानूनी विवाद पटना न्यायिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निपटाये जायेंगे। लेखकों द्वारा व्यक्त विचार उनके अपने है। इसकी जिम्मेदारी उनकी है एवं इसके लिये संपादक, प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नही है। सामग्री की वापसी की जिम्मेवारी उभरता बिहार की नहीं होगी। इस अंक में प्रकाशित सभी रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित है। कुछ छाया चित्र और लेख इंटरनेट, एजेंसी एवं पत्र-पत्रिकाओं से साभार। उपरोक्त सभी पद अस्थायी एवं अवैतनिक है। किसी भी आलेख पर आपत्ति हो तो 15 दिनों के अंदर खंडन करें।

नोट : किसी भी रिपोर्टर द्वारा अनैतिक ढंग से लेन-देन के जिम्मेवार वे स्वयं होंगे।

संरक्षक

डॉ. संतोष कुमार | अखिलेश कुमार जायसवाल

प्रभात कुमार चौधरी | डॉ. राकेश कुमार

मोदी के यू-टर्न के सियासी मायने 09

यह ना खालिस्तानी गुंडों की जीत है... 15

महिलाओं पर सवाल उठाने से ... 31

मातृछाया ऑर्थो एण्ड हेल्थ केयर

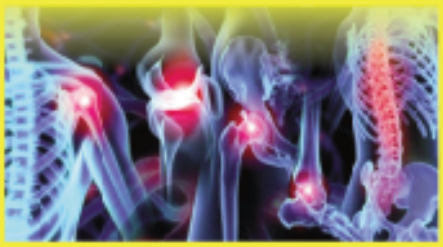

Consultant Trauma & Spinal Surgeon

हड्डी, जोड़, रीढ़, नस एवं गठिया रोग विशेषज्ञ

विशेषता:

1. यहां हड्डी रोग से संबंधित सभी रोगों का इलाज होता है।
2. मशीन के द्वारा टूटे-हड्डी बैठाने की सुविधा उपलब्ध है।

विशेषता:

3. स्पाइन सर्जरी की भी सुविधा है।
4. Total Joint Replacement विशेषज्ञों की टीम के द्वारा सस्ते दरों पर की जाती है।

24 HRS.

ORTHO & SPINAL EMERGENCY

Dr. Rakesh Kumar

M.B.B.S. (Pat), M.S. (Pat), M.Ch.

Ortho Fellowship in Spine Surgery

Indian Spinal Injury Centre, New Delhi

G-43, P.C. Colony, Kankarbagh, Patna-20, Mob. - 7484814448, 9504246216

किसान आंदोलन खत्म होकर राजनैतिक माहौल गरमाया

राजीव रंजन
संपादक
rradvocate@gmail.com

केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये किसानों से सम्बंधित तीनों कानून को वापस लेने के बाद 378 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अब हुआ समाप्त। लंबे आंदोलन के बाद किसान अब दिल्ली बॉर्डर को खाली करेंगे। केन्द्र सरकार की ओर से दिये गये प्रस्ताव पर किसान संगठन की सहमति बनी और किसान संगठनों की तरफ से 09 दिसम्बर (गुरुवार) को आंदोलन स्थगित कर दिया गय।

संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिये गये फैसले के आलोक में 11 दिसंबर (शनिवार) को किसान अपने घर लौटने लगे हैं। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है बल्कि स्थगित हुआ है। छोटे छोटे मोर्चे खत्म हो रहे हैं लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा बरकरार रहेगा और प्रत्येक महीने में 15 तारीख को किसानों के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने के लिए एक बैठक होगी। लेकिन फिलहाल किसानों की घर वापसी निश्चित है। किसान मोर्चा का कहना है कि 15 जनवरी को किसान संगठनों की बैठक होगी। अब देखना होगा कि केन्द्र सरकार किसानों के मौजूदा कानून हटाने के बाद अब किसानों के हित के लिए कौन सा कदम उठाने जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत की केन्द्र सरकार ने कानून वापस लेकर कमर ही तोड़ दिया है। जनता के गलियारों में यह चर्चा आम थी कि टिकैत किसान आंदोलन के कंधे पर विदेशों, विरोधियोंसे पैसा लेकर आपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ था। अब जनता टिकैत की अगली चाल और पहल पर ध्यान रखे हुए हैं। सरकार द्वारा कानून वापस लेने के बाद अचानक राजनीति में उलट फेर शुरू हो गया है।

कृषि कानूनों की वापसी कई उठते नए सवाल

गुरुनानक जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। बीते कई महीनों से जारी किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने किसानों से अब घर लौटने की अपील की और कहा कि इस कानून को खत्म करने प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी तपस्या में ही कमी रही होगी, जिसकी वजह से हम कुछ किसानों को नहीं समझा पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पांच दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की मुश्किलों, चुनौतियों को बहुत करीब से अनुभव किया है।

उभरता बिहार डेस्क

कृषि कानूनों के संदर्भ में पीएम मोदी ने कहा कि बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया।

उन्होंने आगे कहा कि हमारी सरकार, किसानों के कल्याण के लिए, खासकर

छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए, पूरी सत्य निष्ठा से, किसानों के प्रति समर्पण भाव से, नेक नीयत से ये कानून लेकर आई थी। आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।

पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा।

इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। उन्होंने कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए।

तीनों कृषि कानून वापसी के पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद किसानों ने टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर जश्न मनाया। किसानों ने कहा कि गुरुपर्व पर यह उनके संघर्ष की जीत है। किसान संगठनों ने आंदोलन वापस होने पर कुंडली बॉर्डर पर लड्डू बांटे। किसान एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाइयां दे रहे हैं।

भाकियू नेता शमशेर सिंह दहिया ने कहा कि यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। इसमें संयुक्त मोर्चे को बहुत बहुत बधाई है। एक साल बाद देर आए दुरुस्त आए प्रधानमंत्री ने आखिरकार किसानों की मांगें मान ली है, क्योंकि यह एक सच्ची लड़ाई थी।

नए उठते सवाल

इस मामले को इतना समय देना और कुछ अलग तरह के किसानों के दबाव में आने के कारण ये निर्णय लेना पड़ा लगता है। कई राज्यों के चुनाव में भी यह फैक्टर प्रभाव कारी रहा। लगता है भाजपा उत्तर प्रदेश और पंजाबआदिके आसन्न चुनाव में डैमेज कंट्रोल बचाने के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। सरकार पर आगे और तरह के दबाव भी आ सकते हैं। सीएए और यूएपीए का विरोध, संविधान बचाओ देश बचाओ और भी तरह तरह के नारे देकर विपक्ष अपनी जमीन बचाने में लगा है। टिकैत , जयंत सिंह, ममता,शरद पवार तथा शिवसेना आदि जिन्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है।

इस लिए यह प्रयोग देश संविधान और राष्ट्र के संघीय ढांचे के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस कानून की वापसी से भारतीय गणतंत्र, भारतीय संविधान और उन असंख्य जनता का अपमान हुवा है जिन्होंने भारी बहुमत से सरकार को अपना जनमत दिया था। जहां पूरी बहस और वैधानिक प्रक्रिया के जरिए कानून बना था।जिसे अक्षम विपक्ष ने काले कानून की संज्ञा देकर खुद का वजूद मिटा दिया है। अब संसद में सारे घटना क्रम की सफाई देकर विशेषज्ञों की राय से। नया कानून निर्मित किया जा सकता है जिसमें बार्डर सील करने और लाल किले पर देश का अपमान करने वाले तत्व को दूर रखना होगा।

“ पीएम मोदी ने कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। उन्होंने कहा कि आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है।

लाल किले में हुई हिंसा के पीछे का सच

पंजाब में चल रहे किसान आन्दोलन के दरमियान कुछ लोगों ने यह घोषणा की थी कि वे 26 जनवरी 2021 को लाल कि ले में जाकर आन्दोलन का झंडा फहराएँगे । कनाडा-अमेरिका के कुछ अलगाववादी समूहों ने उनको ईनाम देने की घोषणा भी की जो लाल कि ले पर उनका झंडा फहराएँगे । किसान आन्दोलन का नेतृत्व कर रही अनेक जत्थेबंदियों ने स्पष्ट कहा कि वे लाल कि ले पर झंडा फहराने के पक्ष में नहीं हैं । जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनका किसान आन्दोलन से कोई ताल्लुक नहीं है । तब आम लोगों ने समझा था कि लाल कि ले पर इस कि स्म की घटना नहीं हो सकती क्योंकि किसान आन्दोलन के नेतृत्व ने इससे अपना नाता नहीं रखा । इतना ही नहीं इसकी स्पष्ट घोषणा भी की । लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि इस घोषणा के बाद भी यह विवाद शान्त नहीं हुआ ।

एक धारणा तो यह थी कि उग्र तत्वों पर किसान आन्दोलन के नेताओं का कोई नियंत्रण ही नहीं है । इसके विपरीत उग्र तत्व किसान आन्दोलन के नेताओं को दिशा निर्देश देते हैं और आन्दोलन नेतृत्व उसका अक्षरशः पालन करता है । दूसरी धारणा थी कि देश विदेश के कुछ संगठन इस लाल कि ला ग्रुप के पीछे हैं । किसान आन्दोलन का नेतृत्व चाहे इसका समर्थन करे चाहे विरोध करे , इससे कुछ फर्क. पड़ने वाला नहीं है । लाल कि ला ग्रुप अपना काम करके ही रहेगा । लेकिन पर्दे के पीछे के संगठन या समूह कौन से हैं , इस पर आज तक मतैक्य नहीं हो सका है । लाल कि ले पर जो हुआ , उसे यहाँ दोहराने की जरुरत नहीं है । जो ग्रुप वहाँ हुड़दंग मचा रहा था , उसे लगता होगा कि यक ीनन पुलिस गोली चला देगी । जिससे कुछ लोग मारे जाएँगे । राजनीतिज्ञों व अलगाववादियों को अपने षड्यन्त्र में सफल होने के लिए कुछ लाशों की जरुरत होती है । उन पर वे लम्बे समय तक अपनी रोटियाँ सेंकते हैं । लेकिन कि ले में पुलिस खुद

> “ लाल कि ला ग्रुप अपना काम करके ही रहेगा । लेकिन पर्दे के पीछे के संगठन या समूह कौन से हैं , इस पर आज तक मतैक्य नहीं हो सका है । लाल कि ले पर जो हुआ , उसे यहाँ दोहराने की जरुरत नहीं है । जो ग्रुप वहाँ हुड़दंग मचा रहा था , उसे लगता होगा कि यक ीनन पुलिस गोली चला देगी । जिससे कुछ लोग मारे जाएँगे । राजनीतिज्ञों व अलगाववादियों को अपने षड्यन्त्र में सफल होने के लिए कुछ लाशों की जरुरत होती है । उन पर वे लम्बे समय तक अपनी रोटियाँ सेंकते हैं ।

लाल कि ला ग्रुपह्नकी हिंसा का शिकार हो गई लेकिन उसने इस ग्रुप को लाशें नहीं दीं । ग्रुप लाल कि ले में हुड़दंग तो मचा पाया लेकिन इस षड्यन्त्र को आधार बना कर अपनी आगे की रणनीति में कामयाब नहीं हो पाया ।

मुकद्दमे दर्ज हुए । जाँच हो रही है । लेकिन अब पंजाब में विधान सभा चुनाव नजदीक आ रहे है । दो महीने ही बचे हैं । इसलिए लाल कि ला ग्रुप के कारनामों से जो संगठन लाभ लेना चाहता था , वह ज्यादा देर छिप कर नहीं बैठ सकता था । बिल्ली को थैले से बाहर आना ही था । लेकिन थैले से बाहर आने का एक खतरा भी था । आम लोगों को पता चल जाता कि लाल कि ला ग्रुप के पीछे कौन था ? इस रहस्य के उद्घाटित होने का खतरा तो था ही । उधर चुनाव इतने नजदीक और इधर थैली से बाहर आने से छवि खंडित होने का खतरा । परन्तु अब निर्णय तो करना ही था क्योंकि चुनाव को महज दो महीने बचे थे । अन्ततः निर्णय प्रकट होने के पक्ष में ही हुआ । पंजाब की कांग्रेस सरकार ने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर ही दी कि लाल कि ला ग्रुप के एक्शन में फँसे हुए व्यक्तियों को दो दो लाख रुपए की सहायता पंजाब सरकार के बजट में से दी जाएगी । यह कुछ कुछ उसी प्रकार का निर्णय है जिस प्रकार कभी जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति ने निर्णय किया था कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण दंड प्रक्रिया से गुजर रहे विश्वविद्यालयी छात्रों को मुकद्दमा लड़ने के लिए पैसा विश्वविद्यालय देगा ।

पंजाब सरकार के इस निर्णय से यह संकेत तो मिलता ही है कि लाल कि ला ग्रुप के एक्शन प्लान से पंजाब कांग्रेस किसी न किसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बंधित रही होगी । लाल कि ला ग्रुप के एक्शन साधारण नहीं थे । वे पूरे विश्व के सामने देश को अपमानित करने वाले एक्शन थे ।वे क्षणिक उत्तेजना में किया गया कार्य भी नहीं था । उसके लिए पूरी योजना बनाई गई लगती थी । इस योजना को उस समय क्रियान्वित किया गया जब पूरे विश्व की निगाहें इंडिया गेट पर हो रही भारतीय सेना की परेड पर लगी होती है ।लाल कि ले पर हो रही घटनाओं का पूरे विश्व में प्रदर्शन किया जा रहा था । कहीं तो लाईव ही दिखाया जा रहा था । लेकिन यह सब कुछ उस पूरे षड्यन्त्र का प्रथम भाग था । उसका दूसरा भाग अब कांग्रेस सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिखाया है । लाल कि ला ग्रुप के एकेशनकारियो को दो दो लाख की सहायता राशि उस दूसरे भाग का पहला हिस्सा है । हो सकता है कुछ समय बाद इसका दूसरा हिस्सा भी सार्वजनिक किया जाए । वह हिस्सा एकेशनकारियों में से कुछ को विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का टिकट देना भी हो सकता है । सभी के ध्यान में ही है कि जब दो लोगों ने इंदिरा गान्धी की गिरफ़्तारी के विरोध में भारत। करार के एक विमान का अपहरण कर लिया था । बाद में कांग्रेस ने उनको विधान सभा का चुनाव लड़ने के लिए पार्टी टिकट देकर सम्मानित व उत्साहित किया था ।

वैसे तो पंजाब में शुरू से ही लोगों को शक था कि किसान आन्दोलन के नाम से चलाए जा रहे अभियान के पीछे कांग्रेस का ही हाथ था । प्रजातन्त्र में हर राजनीतिक दल को सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाने का अधिकार है । इस पर किसी को एतराज भी नहीं होना चाहिए । विरोध में मत , लोकतन्त्र का प्राण है । लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को आन्दोलन के नाम पर लाल कि ला एक्शन का अधिकार नहीं है । ऐसा एक्शन जो शुद्ध रूप से गुंडागर्दी व हिंसा पर ही आधारित हो । लेकिन पंजाब में चुनाव आ गए हैं । इसलिए कांग्रेस को लगता होगा इन एक्शनकारियों को केवल महिमा मंडित करने भर से काम नहीं चलने वाला । उसके लिए नकद पैसा देना होगा , तभी आगे बढ़ेगी । ये दो दो लाख रुपए देना, इसी रणनीति का हिस्सा है । यह रणनीति सचमुच प्रशासन के लिए महँगी पड़ सकती है । लेकिन कांग्रेस को इससे कुछ फर्क. नहीं पड़ता । उसे तो येन केन प्रकारेण चुनाव जीतना है ।

> “ पंजाब सरकार के इस निर्णय से यह संकेत तो मिलता ही है कि लाल कि ला ग्रुप के एक्शन प्लान से पंजाब कांग्रेस किसी न किसी प्रकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बंधित रही होगी । लाल कि ला ग्रुप के एक्शन साधारण नहीं थे । वे पूरे विश्व के सामने देश को अपमानित करने वाले एक्शन थे ।वे क्षणिक उत्तेजना में किया गया कार्य भी नहीं था । उसके लिए पूरी योजना बनाई गई लगती थी । इस योजना को उस समय क्रियान्वित किया गया जब पूरे विश्व की निगाहें इंडिया गेट पर हो रही भारतीय सेना की परेड पर लगी होती है ।

मोदी के यू-टर्न के सियासी मायने

जो किया किसानों के लिए किया और जो कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ

ये वो लाइनें थीं, जिन्हें सुना बहुत लोगों ने पर समझ में कुछेक के आयेंगी।

यूं अचानक मोदी सरकार ने कृषि कानूनों पर यू-टर्न लिया, ये कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं लगता। लगता है कि इसकी तैयारी बहुत सोच समझ कर की गयी। दरअसल कानून वापस लेना अपने आप में एक बड़ा कदम है, जिसे लेने से पहले हजार बार सोचना जरूरी था। ये ठीक वैसे ही है जैसे शतरंज की चाल चलते समय आपको ध्यान में रखना होता है कि किसी मोहरे को आगे बढ़ाने के बाद प्रतिक्रिया क्या होगी, सिर्फ अगली चाल में ही नहीं बल्कि आने वाली कई सारी चालों में प्रतिद्वन्दी क्या प्रतिक्रिया देगा, ये जिसको नहीं पता वो शतरंज में ही नहीं बल्कि राजनीति की बिसात में भी हार जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में कई वार किये और तमाम लोगों से जमे-जमाये मुद्दों को छीन लिया। हालांकि विपक्ष मान बैठा था कि मोदी सरकार की हठधर्मिता के कारण उनके मुद्दे को हवा-पानी मिलता रहेगा। पहले, ह्यदिनोंह्न से शुरू हुआ ये आन्दोलन कब ह्यमहीनोंह्न में पहुंचा और अब तो ह्यसालह्न भी क्रॉस करके लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाता चला जा रहा था। किसान आन्दोलन के नाम पर पूरे देश और विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब राकेश टिकैत की राजनीति को यहीं से धार मिली और विपक्ष को संजीवनी। एक समय मुद्दों की मुफलिसी झेल रहा विपक्ष का वृक्ष, किसान आन्दोलन के बढ़ते परवान से राजनीतिक रूप से सदाबहार हो चला था। किसान आन्दोलन का गुब्बारा लगातार बड़ा होकर आसमान की बुलंदियों को चुनौती देता नजर आ रहा था, पर अचानक प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह-सुबह आकर उस गुब्बारे की हवा निकाल दी। हर कोई हक्का बक्का था कि अचानक क्या हो गया। आम भाजपाईयों को अपने प्रधानमंत्री से ये उम्मीद नहीं थी कि वो विपक्ष के आगे इस तरह से घुटने टेक देंगे। पर जानकारों की माने तो ये मोदी के तरकश का पुराना तीर है।

इस आन्दोलन को करीब से देखने और उसका विश्लेषण करने वाले बताते हैं

> “इस आन्दोलन को करीब से देखने और उसका विश्लेषण करने वाले बताते हैं कि यह किसान आन्दोलन सिर्फ सरकार के विरोध के लिए खड़ा किया गया था, जिसके लिए फंडिंग विदेशों से आने के आरोप भी लगाये गये थे। इस पूरे आन्दोलन के दौरान कई बार देश में अस्थिरता लाने के कई प्रयास भी हुए, कुछ में आन्दोलनकारी सफल हुए तो कुछ में विफल। चाहे वो इस साल की शुरूआत में लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराने में कामयाब हुए तथाकथित किसानों का मामला हो, या फिर देश में टूलकिट के माध्यम से एक विशेष जंग छेड़ने की तैयारी।

कि यह किसान आन्दोलन सिर्फ सरकार के विरोध के लिए खड़ा किया गया था, जिसके लिए फंडिंग विदेशों से आने के आरोप भी लगाये गये थे। इस पूरे आन्दोलन के दौरान कई बार देश में अस्थिरता लाने के कई प्रयास भी हुए, कुछ में आन्दोलनकारी सफल हुए तो कुछ में विफल। चाहे वो इस साल की शुरूआत में लाल किले में खालिस्तानी झंडा फहराने में कामयाब हुए तथाकथित किसानों का मामला हो, या फिर देश में टूलकिट के माध्यम से एक विशेष जंग छेड़ने की तैयारी। कई उतार-चढ़ाव आये पर किसान आन्दोलन पनपता रहा। और इसी की आड़ में सुलगती रही विपक्षी दलों की राजनीति की आग।

प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही पूरे देश से माफी मांग ली हो पर किसान नेता राकेश टिकैत अब भी माफ करने को तैयार नहीं दिख रहे। अचानक हुई इस अप्रत्याशित घटना से हैरान टिकैत परेशान से नजर आते हैं, पिछले एक साल से अधिक समय से मीडिया ने उन्हें जिस तरह से हाईलाइट किया है, उतना तो वो पूरी जिन्दगी में नहीं हुए। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है, तभी वो आन्दोलन को खत्म करने की बात नहीं कह रहे। उल्टा वो अब उस दिन का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, जिस दिन तीनों कृषि कानून संसद में भी रद्द नहीं हो जाते। इसके अलावा भी वो एमएसपी पर भी सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर इतनी मेहनत से तैयार की गयी जमीन को यूं खिसकता देख राकेश टिकैत में खिसियाहट साफ देखी जा सकती है।

प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के पीछे किसान नेता और विपक्षी दल आने वाले 5 राज्यों के चुनावों का असर बता रहे हैं, और अब फिर से सरकार को इसी यूटर्न पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं पर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, एक समय खराब स्थिति में पहुंच चुकी भाजपा, मुद्दा विहीन और कमजोर विपक्ष के कारण ही वर्तमान स्थिति में काफी हद तक मजबूत हो चुकी है।

उधर कांग्रेस, आन्दोलन के सहारे चुनावी नैया पार लगाने के चक्कर में थी। और यही हाल समाजवादी पार्टी का भी था। जानकार आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊंची छलांग लगाने के लिए चार कदम पीछे हटना पड़ता है, और मोदी सरकार ने भी यही किया हो। क्योंकि जो सरकार तमाम आन्दोलनों से नहीं डरी, लगातार हो रहे हमलों के बावजूद मोदी सरकार ने धैर्य नहीं खोया और इस पूरे किसान आन्दोलन के दौरान किसानों पर सरकार की ओर से कोई भी दमनकारी कदम बढ़ता नहीं दिखाई दिया, पर वो अचानक इस तरह से पीछे हट जायेगी, ये बात कम हजम होती है।

उस पर भी प्रधानमंत्री मोदी का ये कथन, जो किया किसानों के लिए किया और जो कर रहा हूँ वो देश के लिए कर रहा हूँ इस पर आपको भी मंथन करना चाहिये, इस बात के क्या सियासी मायने निकलेंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं।

“ प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान के पीछे किसान नेता और विपक्षी दल आने वाले 5 राज्यों के चुनावों का असर बता रहे हैं, और अब फिर से सरकार को इसी यूटर्न पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं पर राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, एक समय खराब स्थिति में पहुंच चुकी भाजपा, मुद्दा विहीन और कमजोर विपक्ष के कारण ही वर्तमान स्थिति में काफी हद तक मजबूत हो चुकी है। उधर कांग्रेस, आन्दोलन के सहारे चुनावी नैया पार लगाने के चक्कर में थी।

वैक्सीन को चकमा नहीं दे पाएगा ओमिक्रोन : डब्लूएचओ

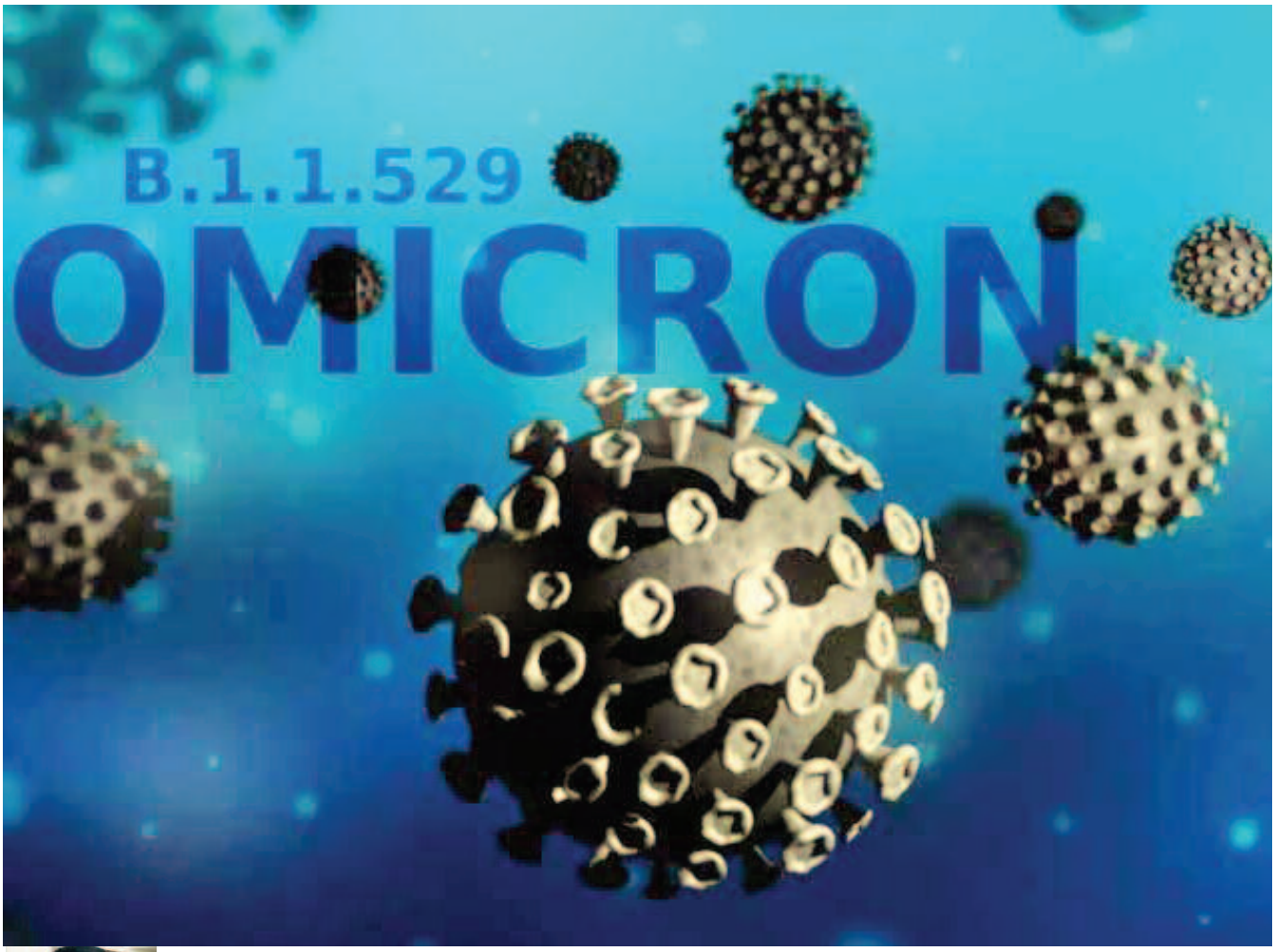

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

डब्लूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) के अनुसार कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन पिछले कोविड वैरिएंट की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी का कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो कोरोना वेरिएंट की सुरक्षा के लिए लगाये जा रहे हैं, उसे ओमिक्रोम पूरी तरह से चकमा नहीं दे सकती है। डब्लूएचओ के दूसरे-इन-कमांड ने बताया है कि कोविड - 19 के नए, भारी रूप से म्यूटेंट वैरिएंट के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है, लेकिन प्रारंभिक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि यह डेल्टा और अन्य वैरिएंट की तुलना में लोगों को ज्यादा बीमार नहीं कर सकती है।

डब्लूएचओ के आपात स्थिति निदेशक माइकल रयान ने एक साक्षात्कार में बताया था कि प्रारंभिक आंकड़े यह संकेत नहीं देते हैं कि यह अधिक गंभीर है। वास्तविकता में जो संकेत मिल रहे हैं वह कम गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे अभी बहुत शुरूआती दिन हैं, लोगों को बहुत सावधान रहना होगा।

उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन मौजूदा कोविड टीकों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को पूरी तरह से दरकिनार या ध्वस्त कर सकता है। भारत द्वारा तैयार किया गया कोवैक्सीन किसी खास स्ट्रेन पर केन्द्रित नही रहने के कारण ओमिक्रोन वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा कारगर हो सकता है। ओमिक्रोन पांचवां "वेरिएंट ऑफ कंसर्न" है और डेल्टा के बाद पिछले सात महीनों में पहला है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पहली बार मिला वायरस का नया रूप ओमिक्रोन का फैलाव विश्व

> डब्लूएचओ के आपात स्थिति निदेशक माइकल रयान ने एक साक्षात्कार में बताया था कि प्रारंभिक आंकड़े यह संकेत नहीं देते हैं कि यह अधिक गंभीर है। वास्तविकता में जो संकेत मिल रहे हैं वह कम गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे अभी बहुत शुरूआती दिन हैं, लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन मौजूदा कोविड टीकों द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को पूरी तरह से दरकिनार या ध्वस्त कर सकता है।

के अनेक देशों में फैल चुका है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नीदरलैंड, इजरायल, हांगकांग, बेल्जियम,आस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्वीडेन, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, पुर्तगाल, सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, यूएसए, नार्वे, घाना, आयरलैंड, नाइजीरिया और यूएई प्रमुख है।

कोरोना के नये रूप ओमिक्रोन का खतरा भारत में भी मडराने लगा है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल और बोत्सवाना में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। भारत में ओमिक्रोन के मामले सामने आने के बाद केन्द्र सरकार हरकत में आ गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित दो मरीज पाए गए हैं। एक संक्रमित मरीज कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका है, जबकि एक मरीज ने वैक्सीन की पहली डोज ली है। पहले संक्रमित मरीज की उम्र 66 वर्ष बताई जा रही है, जिसने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया था और वहीं दूसरा संक्रमित मरीज 46 साल का स्वास्थ्यकर्मी है जिसने कोई यात्रा नहीं की है। कोरोना वायरस के डेल्टा वैरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन वैरिएंट को भारत में पांच गुना अधिक संक्रामक बताया जा रहा। विशेषज्ञ के अनुसार, ओमिक्रॉन में कोरोना वायरस का सबसे अधिक म्यूटेट वर्जन देखने को मिला रहा है। इसी कारण वैज्ञानिक कोरोना वायरस के इस नए वैरिएंट को लेकर चिंतित हैं।

कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन बिहार में भी पहुंच गया है इसकी सूचना मिल रही है। ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के लक्षणों को जानने के लिए जुटाए गए शुरूआती डेटा के अनुसार, ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित मरीजों को बहुत अधिक थकान, गले में खराश, मांशपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं आती हैं। जबकि ओमिक्रोन से संक्रमित व्यक्ति के स्वाद और गंध की क्षमता में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है।

ओमिक्रोन का पता लगाने वाली दक्षिण अफ्रीका के चिकित्सकों का कहना है कि फिलहाल मरीजों में हल्के लक्षण ही देखे जा रहे है। इस वैरिएंट से संक्रमित लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़े है।

भारत में ओमिक्रोन वैरिएंट से बचने के लिए लोगों को कोविड-19 की दोनों डोज लेना जरूरी बताया जा रहा है। पूर्व की तरह ही सामाजिक दूरी का पालन करना और नियमित अंतराल पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का सलाह दी जा रही है। उसी तरह सार्वजनिक जगहों पर जाने से पहले मास्क का प्रयोग करने और जरूरी न होने पर यात्रा करने से और भीड़ वाले इलाकों में जाने से परहेज करने तथा नियमित अंतराल पर हाथों को भी अच्छे से धोने का सलाह दिया जा रहा है।

नये खतरे को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार अपनी अपनी तैयारियों का आकलन करने लगी है। लोगों को यह नही भूलना चाहिए कि भारत में महामारी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर भी पहल किया जाता है। इसलिए लोगों को कोविड-19 से सम्बंधित सभी उपायों का पालन करना चाहिए। भारत में अब पर्याप्त टीके बन रहे हैं। बूस्टर खुराक दिये जाने के वैज्ञानिक तर्क का भी अध्ययन किया जा रहा है।

“कोरोना के नये रूप ओमिक्रोन का खतरा भारत में भी मडराने लगा है। दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, पुर्तगाल और बोत्सवाना में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आए हैं। भारत में ओमिक्रोन के मामले सामने आने के बाद केन्द्र सरकार हरकत में आ गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन से संक्रमित दो मरीज पाए गए हैं। एक संक्रमित मरीज कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुका है।

राजनीतिक गलियारों में जीकेसी की चर्चा तेज

GLOBAL KAYASTHA CONFERENCE

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, प्रदेश उपाध्यक्ष, जीकेसी, बिहार

जीकेसी (ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेन्स) ने कायस्थ समाज के लिए सेवा, सहयोग, संप्रेषण, सरलता, समन्वय, सकारात्मकता और संवेदनशीलता का भावना लेकर संगठन बनाया है और इसी आधार पर संगठन को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहा है। पूरी दुनियाँ में मकड़जाल की तरह संगठन का विस्तार और विस्तृत आकार दिया जा रहा है। इसी क्रम में ग्लोबल अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद एकतासूत्र में कायस्थ समाज को बांधने के लिए देश के राज्यों में, जिलों में स्वयं और अपने संगठन के सभी संवर्ग के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को साथ लेकर तथा उन पदाधिकारियों द्वारा अलग-अलग लोगों के बीच जाकर गोलबंद करने में जुट गये हैं और यह प्रयास निरंतर चलता रहेगा।

समाज के वैसे कायस्थ परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन वसर कर रहे है, उनकी निःस्वार्थ भाव से देखभाल करना और उसे एकता की सूत्र में बांधे रखने का उद्देश्य रखता है सेवा। स्वामी तुलसीदास जी का कथन है कि ह्यपरहित सरिस धर्म नहीं भाईह्ण अर्थात दूसरों की भलाई के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, यानि आवश्यकता पड़ने पर निःस्वार्थ भाव से दूसरो को सहयोग देना ही परोपकार है। इसलिए जीकेसी का पहला संकल्प है सेवा।

संतुलित विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, सहयोग की आदते मनुष्य में मैत्री भावना को विकसित करती है। इसलिए सहयोग की भावना मनुष्य में होना अति आवश्यक होता है। काई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति और समाज का कल्याण सहयोग पर ही आधारित होता है। इसलिए जीकेसी का दूसरा संकल्प है सहयोग।

अपने विचारों, तथ्यों तथा भावनाओं का आदान-प्रदान करना, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। प्रत्येक संगठन का रीढ़ होता है सम्प्रेषण। सम्प्रेषण किसी भी संस्थान, व्यक्ति की छवि, संस्थान का महत्व और विश्वास को समाज में स्थापित करने में सहयोगी होता है, यानि कहने का तात्पर्य है कि संप्रेषण जनता-संगठन और व्यक्ति के बीच सेतु का काम करता है। इसलिए जीकेसी का तीसरा संकल्प है संप्रेषण।

संगठन की सादगी, धैर्य और करूणा को अपने-अपने कर्मों, विचारों एवं व्यवहारों में लाकर जटिल कार्यों और बाधाओं को सरलता से पार कर कायस्थ समाज को संगठित करने के उद्देश्य से जीकेसी का चौथा संकल्प है सरलता है।

अनेकता में एकता की स्थापना करना, व्यक्तियों और संगठनों को एकीकृत करना, व्यक्ति, प्रकोष्ठ और संगठनात्मक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाये रखना, सकारात्मक रूप से प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों और जनता के बीच समन्वय कायम रखना। इसलिए जीकेसी का पांचवां संकल्प है समन्वय।

सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास, आचार-विचार को जीवन में आकार देना, भौतिक बदलाव लाना, आत्म विश्वास, दृढ़संकल्प, दृढ़ता और कड़ी मेहनत करने पर वल देना, स्थिति की परवाह किये बिना खुशी, स्वास्थ्य और एक सुखद जीवनयापन करने में मदद करना। इसलिए जीकेसी का छठ्ठा संकल्प है सकारात्मकता।

एक दूसरे के भावनाओं एवं पीड़ा को समझना, देश के प्रति संवेदनशील और इमानदार होना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन वसर कर रहे कायस्थ समाज के लोगों को आर्थिक रूप से पढ़ाई-दवाई, परिवारिक, सामाजिक, नैतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से जीकेसी का अंतिम और सातंवा संकल्प है संवेदनशीलता।

जीकेसी अपने इन सात संकल्पों के साथ निरंतर गतिशील है और देश दुनियाँ को यह दिखाने और समझाने में प्रयासरत है कि हम कायस्थ समाज एक है और हमारी एकता ही हमारी बल है। हम कामयाब थे, हैं और रहेगे।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, अपनी सेवा, लगन और साधनामय जीवन, विषाल एवं विलक्षण व्यक्तित्व, योग्यता, नम्रता, सच्चाई, सरलता, निस्पृहता और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिला स्थित जीरादेई ग्राम में 03 दिसम्बर, 1884 को एक सम्पन्न कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी ऐसी ही कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

> “पाकिस्तान की लम्बी सीमा पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ लगती है । पंजाब की सीमा भी अपने पड़ोसी राज्य जम्मू से मिलती है । पाकिस्तान भारत को अस्थिर करना चाहता है , इसमें भी कोई शक नहीं है । सिद्धु और चन्नी से बेहतर इसको कौन जान सकता है । पंजाब में उसने आतंकवाद को जन्म दिया और उसे पाला पोसा । शुरू में कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मौन बनी रही ।

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 12 वर्षों तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया, अलंकृत किया और राष्ट्रपति पद की गुण-गरिमा को बढ़ाया। डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के संबंध में डॉ० राधाकृष्णन की उक्ति थी कि उनमें जनक, बुद्ध, और महात्मा गाँधी की छाप थी अक्षरशः सत्य है। हमारे कायस्त समाज के पुरोधा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, सम्पूर्ण क्रांति के मसीहा, समाजवादी आन्दोलन के जनक, जन-जन के कंठहार लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म सारण जिलान्तर्गत सिताब दिया गाँव में 11 अक्तूबर, 1902 को हुआ था। लोकनायक सेवा, त्याग, लगन, साधनामय जीवन, विराट यश और अपूर्व गौरव अर्जित कर, विशाल एवं

विलक्षण व्यक्तित्व, नम्रता, सच्चाई, सरलता और निस्पृहता की कहानी आज भी इतिस के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि समाज के फोड़े हैं। समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में अनेक गलत मूल्य है। मूल्य बदले बिना समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए समस्याओं के निराकरण के लिए उनकी जड़ तक जाना होगा। हमें सम्पूर्ण व्यवस्था को जड़ से बदलने का प्रयास करना होगा। वैसे तो कायस्थ समाज के पुरोधाओं की एक लम्बी सूची है जिसमें सर्वसम्मान के साथ लाल बहादुर शास्त्री, स्वामी विवेकानन्द, सुभाष चन्द्र बोस, राजेन्द्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को लोग आसानी से जानते हैं और समझते हैं। जीकेसी का बागडोर राजीव रंजन प्रसाद और रागनी रंजन के हाथ में है। राजीव रंजन प्रसाद और रागनी रंजन को साथ देने के लिए ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेन्स के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने कदम से कदम मिलाकर एकता की सूत्र में कायस्थ समाज को पिरोने का काम निरंतर कर रहे है। उनकी हौसला हरजाई करने के लिए राजीव रंजन प्रसाद और रागनी रंजन ने समय-समय पर दूरभाष से या बैठक आहूत कर दिशा-निर्देश दे रहे हैं और लोग उनके निर्देशन में आगे बढ़ रहे हैं।

वर्तमान राजनीतिक गलियारों में जीकेसी की चर्चा आम बात हो गयी है। इनकी कार्यप्रणाली, लोगों के बीच समन्वयन, सहयोग आदि की चर्चा करते अक्सर राजनीतिक गलियारों में देखा सुना जा सकता है। वो दिन दूर नहीं है जब जीकेसी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ते हुए अपने पूवर्जो के किये गये कार्यों का लोहा आज के दिनों में भी कर के मनवाने में सफल होंगे।

> “ लोकनायक सेवा, त्याग, लगन, साधनामय जीवन, विराट यश और अपूर्व गौरव अर्जित कर, विशाल एवं विलक्षण व्यक्तित्व, नम्रता, सच्चाई, सरलता और निस्पृहता की कहानी आज भी इतिस के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि हिंसा, बेईमानी, भ्रष्टाचार आदि समाज के फोड़े हैं। समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में अनेक गलत मूल्य है। मूल्य बदले बिना समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

यह ना खालिस्तानी गुंडों की जीत है और ना मास्टर स्ट्रोक

यह ना खालिस्तानी गुंडों की जीत है, ना उन गुंडों के आगे सरकार का समर्पण है। ना ही यह कोई चुनावी स्टंट है। ना ही कोई मास्टर स्ट्रोक है।

हम सब जानते है कि 11 महिने पहले सुप्रीम कोर्ट में 12 जनवरी को किसान कानूनों पट स्टे लगा दिया था। एक कमेटी बना दी थी। इसके 14 दिन बाद लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय अस्मिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई गयी। लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा जो मोदी सरकार के 7 वर्ष के शासनकाल में स्वतः संज्ञान लेने का वर्ल्डरिकॉर्ड बना चुका है।

किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी गुंडों के कैंपों में हत्या भी हुई, बलात्कार भी हुआ, आत्महत्या भी हुई लेकिन सुप्रीमकोर्ट खामोश रहा।

किसान आंदोलन के नाम पर कुछ सौ या कुछ हजार गुंडे लगभग साल भर से लाखों नागरिकों का रास्ता रोक कर उनका जीना हराम करते रहे लेकिन लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा जो एक आतंकी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने की सुनवाई रात भर करता रहा। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन किसान कानूनों पर सुनवाई की फुर्सत कोर्ट को नहीं मिली। उसने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी क्या कर रही है। पिछले 10-11 महीनों में उस कमेटी ने क्या किया.? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सम्भवतः अब वह समय आ गया था जब इस खेल का पर्दा उठने वाला था। उपरोक्त घटनाक्रम यह संकेत दे रहा था कि किसान कानून का भी वही हश्र होने वाला है जो हश्र संसद द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति के कानून का किया गया था। ऐसा होने पर सरकार को बहुत अधिक शर्मिंदगी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता। वह स्थिति अब भी हुई है। लेकिन उतनी अधिक नहीं हुई है।

अतः मेरा मानना है कि सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री को इस पूरे खेल का आभास हो गया था। या यूं कहूं कि सूचना मिल गयी थी कि क्या खेल होने जा रहा है। चार राज्यों के चुनावों से पहले होने जा रहा है। अतः उसने सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग को चुना है। जो प्रधानमंत्री नोटबंदी सरीखे ऐतिहासिक साहसिक फैसले से पीछे नहीं हटा। जो प्रधानमंत्री 370 की समाप्ति सरीखे ऐतिहासिक साहसिक फैसले से पीछे नहीं हटा। जो प्रधानमंत्री एक नहीं 2 बार पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके जबड़े तोड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटा। जिस प्रधानमंत्री के शौर्य का उल्लेख पाकिस्तानी संसद में इस जिक्र के साथ हुआ हो कि उसके डर से पाकिस्तानी आर्मी चीफ और विदेश मंत्री की टांगे कांप रहीं थी। वह प्रधानमंत्री कुछ सौ या कुछ हजार खालिस्तानी गुंडों और उनके गुर्गों के आंदोलन से डर गया। यह सोच कुछ कायर कुटिल धूर्तों की हो सकती है। मैं ऐसा नहीं सोचता। कॉलेजियम सिस्टम की समाप्ति वाले कानून का हश्र देख चुके प्रधानमंत्री ने सही निर्णय लिया है। इस सरकार, उसके समर्थकों के खिलाफ देश में कैसा लीगल ज़िहाद चल रहा है। यह नजारा अभी 15 दिन पहले दीपावली पर हम सब ने देखा है। अतः ज्ञान उपदेश प्रवचन नहीं दीजिए। इस कठिन समय समय में देश के प्रधानमंत्री का खुलकर समर्थन करिए। प्रचंड समर्थन करिए। हम भी यही कर रहे हैं , आप भी कीजिए।

“किसान आंदोलन के नाम पर कुछ सौ या कुछ हजार गुंडे लगभग साल भर से लाखों नागरिकों का रास्ता रोक कर उनका जीना हराम करते रहे लेकिन लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा जो एक आतंकी याकूब मेमन की फांसी रुकवाने की सुनवाई रात भर करता रहा। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं। लेकिन किसान कानूनों पर सुनवाई की फुर्सत कोर्ट को नहीं मिली। उसने एक कमेटी बना दी, वो कमेटी क्या कर रही है। पिछले 10-11 महीनों में उस कमेटी ने क्या किया.? इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

आर्थिक मोर्चे पर अंततः सेवा क्षेत्र से भी आई अच्छी खबर

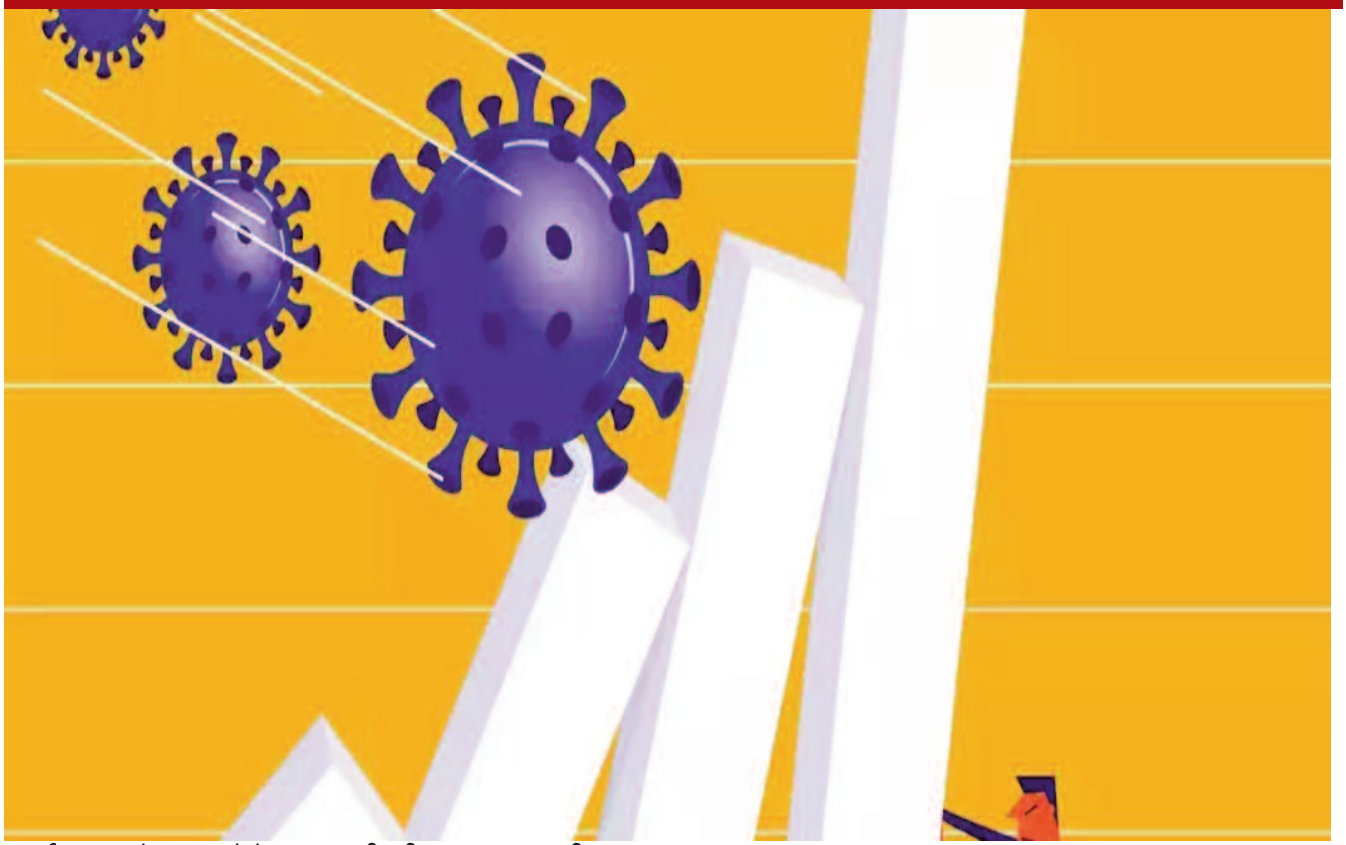

मार्च 2020 के बाद कोरोना महामारी की प्रथम एवं दूसरी लहर के दौरान देश के नागरिकों ने न केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना किया बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी भारी कमी देखने में आई जिसके चलते कई नागरिकों ने अपना रोजगार खोया एवं आर्थिक समस्याओं का सामना किया। परंतु, केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए कई निर्णयों के चलते एवं भारतीय संस्कारों के बीच देश के नागरिकों ने इस बुरे समय का बहुत ही हिम्मत के साथ सामना किया एवं न केवल स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं, साथ ही आर्थिक समस्याओं के प्रभाव को भी कम करने में सफलता पाई थी। अब, जब विशेष रूप से कोरोना महामारी की दूसरी लहर का प्रभाव कम होता जा रहा है तब इसके बाद भारत में आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार दृष्टिगोचर है एवं आर्थिक मोर्चे पर लगातार अच्छी खबरों का आना जारी है।

कोरोना महामारी के दौरान देश का उद्योग एवं सेवा क्षेत्र सबसे अधिक विपरीत रूप से प्रभावित हुआ था। यातायात, होटेल, पर्यटन एवं निर्माण के क्षेत्र तो लगभग बंद ही हो गए थे। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उक्त क्षेत्र आज भी पूरे तौर पर उबर नहीं पाए हैं। आज देश में कोरोना महामारी के पूर्व के अर्थव्यवस्था के स्तर के 95.6 प्रतिशत भाग को प्राप्त कर लिया गया है परंतु व्यापार, होटल, यातायात, संचार एवं ब्रॉड्कास्टिंग से संबंधित सेवा क्षेत्र में अभी भी केवल 80 प्रतिशत के स्तर को ही प्राप्त किया जा सका है। परंतु, अब हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि अक्टोबर 2021 एवं नवम्बर 2021 माह में मांग के बढ़ने से सेवा क्षेत्र में भी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ी हैं। चीन एवं जापान के बाद एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत में, सेवा क्षेत्र में पिछली तिमाही में मांग सबसे तेज गति से आगे बढ़ी है। यह देश में कोरोना टीकाकरण के कार्यक्रम में आई तेजी एवं केंद्र सरकार द्वारा

> “कोरोना महामारी के दौरान देश का उद्योग एवं सेवा क्षेत्र सबसे अधिक विपरीत रूप से प्रभावित हुआ था। यातायात, होटेल, पर्यटन एवं निर्माण के क्षेत्र तो लगभग बंद ही हो गए थे। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। उक्त क्षेत्र आज भी पूरे तौर पर उबर नहीं पाए हैं। आज देश में कोरोना महामारी के पूर्व के अर्थव्यवस्था के स्तर के 95.6 प्रतिशत भाग को प्राप्त कर लिया गया है ।

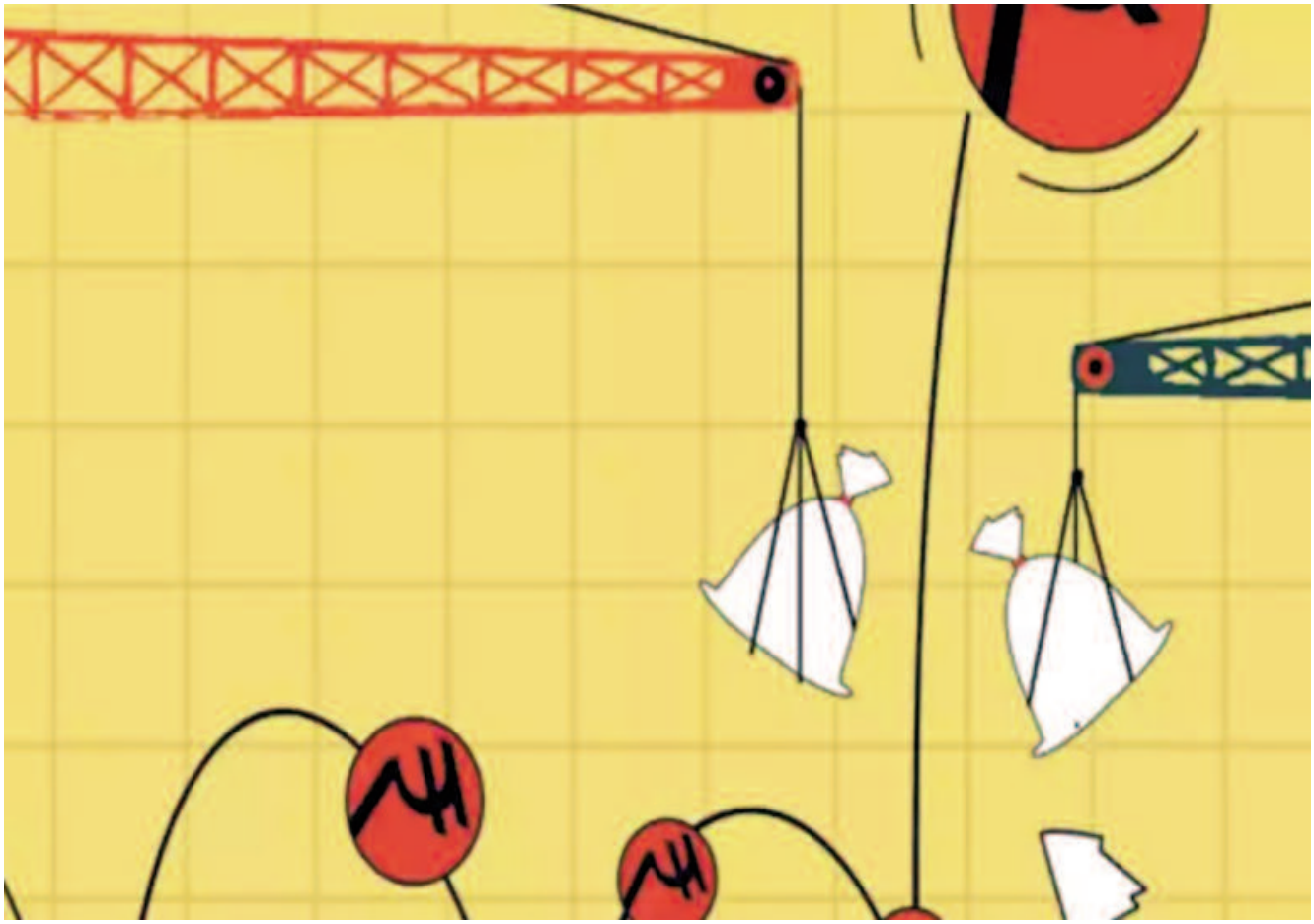

अपने खर्चों में की गई बढ़ोतरी के चलते सम्भव हो पाया है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए सर्विसेज परचेसिंग मेनेजर्स इंडेक्स अक्टोबर 2021 एवं नवम्बर 2021 माह में क्रमशः 58.4 एवं 58.1 के स्तर पर बना रहा है। 58.4 का स्तर तो किसी भी माह में, पिछले दस वर्षों के दौरान, दूसरे स्थान पर सबसे अधिक पाया गया है। इस इंडेक्स का 50 के स्तर से अधिक होने का तात्पर्य वृद्धि होने के संकेत के रूप में माना जाता है। अक्टोबर 2021 माह में विभिन्न त्योहारों के दौरान देश के इतिहास में प्रथम बार क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की गई है। अक्टोबर 2021 माह में क्रेडिट कार्ड के मध्यम से सितम्बर 2021 (80,477 करोड़ रुपए) की तुलना में 25 प्रतिशत एवं अक्टोबर 2020 (64,892 करोड़ रुपए) की तुलना में 56 प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। जबकि कोरोना महामारी के पूर्व के समय में जनवरी 2020 एवं फरवरी 2020 माह में क्रमशः 67,402 करोड़ रुपए एवं 62,903 करोड़ रुपए की राशि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खर्च की गई थी। इसका आशय यह है कि देश के नागरिकों द्वारा अब वस्तुओं की क्रय राशि का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अधिक किया जा रहा है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्रतिवेदन के अनुसार, 19 नवम्बर 2021 को समाप्त एक वर्ष के समय में बैंकों की ऋणराशि में 6.97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। बैंकों की ऋण राशि का स्तर पिछले वर्ष के 104.34 लाख करोड़ रुपए की राशि से बढ़कर 19 नवम्बर 2021 को 111.62 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। इसका आशय यह है कि देश की आर्थिक गतिविधियों में तेजी आती दिखाई दे रही है। बैंकों का भी अपना आकलन है कि अक्टोबर एवं नवम्बर माह में त्योहारों के चलते उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग एवं सेवा) में प्रदान किए जाने वाले ऋणों की गतिविधियों में तेजी आई है। उधर विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भी लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि अब भारत से निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इससे देश के चालू खाता घाटा पर दबाव दिखाई देने लगा है। नवम्बर 2021 माह में देश से निर्यात 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,988 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे जबकि देश में आयात 57.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 5,315 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे। इस प्रकार नवम्बर 2021 माह में चालू खाता घाटा 2,327 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भावों में आई तेजी, त्योहारों के दौरान स्वर्ण के आयात में तेजी एवं देश में आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी के कारण नवम्बर 2021 माह में आयात में बहुत अधिक वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। एक आकलन के अनुसार, केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारों द्वारा जिस रफ्तार से पूंजीगत खर्चे किए जा रहे हैं, यह इस वर्ष के अंत तक कोरोना महामारी के पूर्व (वित्तीय वर्ष 2020) के स्तर को पार करते हुए 12 प्रतिशत आगे निकल जाएंगे। यह देश के लिए एक अच्छी खबर है। क्रिसिल द्वारा जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार, भारत पूंजीगत खर्चों के मामले में कोरोना महामारी के प्रभाव से बहुत जल्दी बाहर निकल आया है। केंद्र सरकार के पूंजीगत खर्चे तो 31 प्रतिशत अधिक हो रहे हैं, अब समस्त राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार के साथ कदमताल करते हुए इस मामले में आगे बढ़ना जरूरी है।

“उधर विदेशी व्यापार के मोर्चे पर भी लगातार सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि अब भारत से निर्यात की तुलना में आयात अधिक तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इससे देश के चालू खाता घाटा पर दबाव दिखाई देने लगा है। नवम्बर 2021 माह में देश से निर्यात 26.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 2,988 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे जबकि देश में आयात 57.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 5,315 करोड़ अमेरिकी डॉलर के रहे।

केंद्र सरकार द्वारा भारत में लागू की गई वित्तीय समावेशन योजना के लाभ दिखने लगे हैं

किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के सम्बंध में ठोस नीतियों को लागू कर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है, गरीबी एवं आर्थिक असमानता को कम किया जा सकता है एवं वित्तीय स्थिरिता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। भारत में भी केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू कर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया है। देश में डिजिटल बैंकिंग के लिए आधारभूत संरचना का विकास करते हुए, बैंकों की शाखाओं को ग्रामीण स्तर तक ले जाने की योजना पर काम किया गया है एवं बैंकिंग संवाददाता (बैंकिंग करेसपोंडेंट) मॉडल को योजनाबद्ध तरीके से देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए उक्त कदमों का परिणाम यह हुआ है कि भारत में प्रति 1000 वयस्क लोगों की जनसंख्या पर इंटरनेट बैंकिंग के लेनदेन जो वर्ष 2015 में 183 थे वह 2019 में बढ़कर 13,615 हो गए हैं। साथ ही, प्रति 100,000 की जनसंख्या पर वर्ष 2015 में बैंक शाखाओं की संख्या 13.5 थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.7 हो गई है, इस प्रकार भारत ने चीन, जर्मनी एवं दक्षिणी अफ्रीका को वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया है।

देश के दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग करेसपोंडेंट मॉडल को बहुत ही सफल तरीके से लागू किया गया है। देश के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग करेसपोंडेंटस की संख्या मार्च 2010 में 34,174 से बढ़कर दिसम्बर 2020 में 12.4 लाख तक पहुंच गई है। इन बैंकिंग करेसपोंडेंटस के माध्यम से स्थानीय निवासियों को सप्ताह में कम से कम 5 दिनों तक, प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके साथ ही, देश के ग्रामीण इलाकों में विभिन्न बैंकों के शाखाओं की संख्या भी मार्च 2010 के 33,378 से बढ़कर दिसम्बर 2020 में 55,073 हो गई है।

वर्ष 2014 में लागू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत पिछले 7 वर्षों के दौरान अभी तक 43.7 करोड़ खाते देश के विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं, दिनांक 20 अक्टोबर 2021 को इन खातों में 1.46 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। उक्त वर्णित खातों में से दो तिहाई खाते देश के ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में चालू थे। 78 प्रतिशत से अधिक खाते देश के सरकारी क्षेत्र की बैंकों में खोले गए हैं, 18.2 प्रतिशत खाते देश की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खोले गए हैं एवं शेष 3 प्रतिशत खाते अन्य वित्तीय संस्थाओं में खोले गए हैं।

सामान्य तौर पर वित्तीय समावेशन की सफलता का आंकलन इस बात से हो सकता है कि सरकार द्वारा इस सम्बंध में बनायी जा रही नीतियों का लाभ समाज के हर तबके, मुख्य रूप से अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक, पहुंच रहा है। भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे। जबकि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 1947 में देश की

> “केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए उक्त कदमों का परिणाम यह हुआ है कि भारत में प्रति 1000 वयस्क लोगों की जनसंख्या पर इंटरनेट बैंकिंग के लेनदेन जो वर्ष 2015 में 183 थे वह 2019 में बढ़कर 13,615 हो गए हैं। साथ ही, प्रति 100,000 की जनसंख्या पर वर्ष 2015 में बैंक शाखाओं की संख्या 13.5 थी जो वर्ष 2020 में बढ़कर 14.7 हो गई है।

आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में आई है। केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से तो वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन में बहुत अधिक सुधार देखने में आया है। उसके पीछे मुख्य कारण देश में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल प्लैट्फार्म पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जब यह योजना प्रारम्भ की जा रही थी तब कई लोगों द्वारा यह सवाल उठाए गए थे कि देश में पहिले से ही इस तरह की कई योजनाएं मौजूद हैं, फिर इस एक और नई योजना को शुरू करने की क्या जरूरत है? अब उक्त योजना की महत्ता समझ में आती है जब जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों देशवासियों के खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं एवं इन खातों में आज सीधे ही सब्सिडी का पैसा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। मनरेगा योजना की बात हो अथवा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की बात हो, पहिले ऐसा कहा जाता था कि केंद्र से चले 100 रुपए में से शायद केवल 8 रुपए से 16 रुपए तक ही अंतिम हितग्राही तक पहुंच पाते हैं, परंत आज हितग्राहियों के खातों में सीधे ही सहायता राशि के जमा हो जाने के कारण बिचोलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो गई है एवं हितग्राहियों को पूरा का पूरा 100 प्रतिशत पैसा उनके खातों में सीधे ही जमा हो रहा है। यह वित्तीय समावेशन की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है। वित्तीय समावेशन के कुछ अन्य लाभ भी देश में देखने में आए हैं जैसे हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार, जिन राज्यों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अधिक खाते खोले गए हैं तथा वित्तीय समावेशन की स्थिति में सुधार हुआ है, उन राज्यों में अपराध की दर में कमी आई है तथा इन राज्यों में अल्कोहल एवं तंबाखु के सेवन में भी कमी आई है।

वित्तीय समावेशन में एक दूसरा पहलू भी है। वह यह कि देश के नागरिकों के बीच वित्तीय साक्षरता को कितना अधिक से अधिक फैलाया जा रहा है। वितीय सक्षरता के मामले में अभी हमारा देश बहुत पीछे हैं। देश का आम नागरिक अभी भी बैंक खातों एवं बीमा योजनाओं का सही सही मतलब नहीं समझ पाता है। शेयर बाजार के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। यह गलती, दरअसल आम नागरिकों की नहीं है। इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं क्योंकि इस ओर अभी तक हमने बहुत गम्भीरता से ध्यान ही नहीं दिया है। वितीय समावेशन का अधिक फायदा तभी हो सकता है जब वित्तीय साक्षरता भी हो। केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल के कारण वित्तीय समावेशन का पहिला भाग तो देश में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है तथा इसे और मजबूत किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं परंतु अब दूसरे भाग की ओर भी उसी गम्भीरता से हम सभी को मिलकर ध्यान देना होगा। तब जाकर वित्तीय व्यवस्था में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

> “ देश में वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में आई है। केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से तो वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन में बहुत अधिक सुधार देखने में आया है। उसके पीछे मुख्य कारण देश में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल प्लैट्फार्म पर ले जाना है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ।

द्वितीय तिमाही में उम्मीद से बेहतर रही है आर्थिक वृद्धि दर

कोरोना महामारी के दूसरे दौर के बीच, वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी का दौर जारी रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जुलाई-सितम्बर 2021 तिमाही में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सबसे अधिक है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 20.1 प्रतिशत की रही थी, परंतु यह वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम तिमाही में कोरोना महामारी के प्रथम दौर के कारण सकल घरेलू उत्पाद में आई 24.4 प्रतिशत की भारी कमी के कारण रही थी।

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही के दौरान कृषि क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दिया था परंतु अब वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही में उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से भी अर्थव्यस्था को भरपूर सहारा मिला है। कृषि क्षेत्र में इस दौरान 4.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है वहीं उद्योग क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि तथा सेवा क्षेत्र में 10.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की अर्द्ध वार्षिक (अप्रेल-सितम्बर 2020) अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 11.4 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई थी क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अप्रेल एवं मई 2020 के दौरान देश में पूर्ण लॉकडाउन एवं जून-सितम्बर 2020 की अवधि में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था। परंतु अब हर्ष का विषय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की अर्द्ध वार्षिक (अप्रेल-सितम्बर 2021) अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। इस प्रकार, अभी भी शेष 3.2 लाख करोड़ रुपए की हानि को पूर्ण करने के लिए इस राशि की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2021-22 के शेष अवधि में प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2021-22 की द्वितीय तिमाही में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है परंतु अभी भी कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक विपरीत रूप से प्रभावित क्षेत्रों यथा, व्यापार, होटल, यातायात, संचार एवं ब्रॉड्कास्टिंग से संबंधित सेवा क्षेत्रों में तेजी आना शेष है और इन क्षेत्रों में 2.6 लाख करोड़ रुपए की हानि की पूर्ति किया जाना है। आज देश में कोरोना महामारी के पूर्व के अर्थव्यवस्था के स्तर के 95.6 प्रतिशत भाग को प्राप्त कर लिया गया है परंतु व्यापार, होटल, यातायात, संचार एवं ब्रॉड्कास्टिंग से संबंधित सेवा क्षेत्र में अभी भी केवल 80 प्रतिशत के स्तर को ही प्राप्त किया जा सका है। अब यह सम्भावना व्यक्त की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही के दौरान अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में कोरोना महामारी के पूर्व के स्तर को प्राप्त कर उक्त वर्णित 3.2 लाख करोड़ रुपए की शेष हानि को भी पूर्ण कर लिया जाएगा।

एक और उत्साहवर्धक खबर निवेश के क्षेत्र से भी आई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम सात माह (अप्रेल-अक्टोबर 2021) के दौरान ही 8.6 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 की पूर्ण अवधि में 11 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में निजी निवेश का योगदान 67 प्रतिशत अर्थात 5.80 लाख करोड़ रुपए का रहा है अतः लम्बे अंतराल के बाद अब निजी निवेश का योगदान भी देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ने लगा है, वरना अभी तक तो मुख्य रूप से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा ही देश में निवेश पर खर्च किया जा रहा था। इसी बीच 29 नवम्बर 2021 को समाप्त सप्ताह में भारतीय स्टेट बैंक का बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स भी 110.7 के स्तर पर आ गया है जिसका आशय यह है कि देश में आर्थिक गतिविधियों ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। इसके साथ ही, 22 अक्टोबर 2021 से 5 नवम्बर 2021 की

पाक्षिक अवधि के दौरान समस्त शिडयूलड कामर्शीयल बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋणों की राशि में 1.18 लाख करोड़ रुपए (7.1 प्रतिशत) की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की 5 नवम्बर तक की अवधि तक 2.14 लाख करोड़ की वृद्धि का 56 प्रतिशत है। उक्त वर्णित पाक्षिक अवधि में अर्थव्यस्था के लगभग समस्त क्षेत्रों (व्यक्तिगत ऋण, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र, आदि) में ऋण प्रदान करने की गतिविधि में महत्वपूर्ण तेजी दृष्टिगोचर हुई है। इसका आशय यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय तिमाही में भी आर्थिक गतिविधियों में तेजी का दौर जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्द्धवार्षिक अवधि के दौरान दर्ज की गई प्रभावशाली विकास दर को जारी रखते हुए अक्टोबर 2021 में उद्योग क्षेत्र के 8 मूलभूत उद्योगों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला, सीमेंट, रीफायनिंग एवं गैस उत्पादन उद्योगों में उत्साहवर्धक वृद्धि दर्ज हुई है। सेमेंट उद्योग में तो 14.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है इसका आशय यह है कि देश में निर्माण का कार्य रफ्तार पकड़ता जा रहा है। अभी आगे आने वाले समय में चूंकि केंद्र सरकार अधोसंरचना के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि का पूंजीगत खर्च करने जा रही है अतः सीमेंट एवं स्टील उद्योग में विकास दर और भी रफ्तार पकड़ेगी।

> “ वित्तीय वर्ष 2020-21 की अर्द्ध वार्षिक (अप्रेल-सितम्बर 2020) अवधि में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 11.4 लाख करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई थी क्योंकि कोरोना महामारी के चलते अप्रेल एवं मई 2020 के दौरान देश में पूर्ण लॉकडाउन एवं जून-सितम्बर 2020 की अवधि में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था।

गांजा तस्करों की कमर तोड़ने में जुटे विनोद दुबे

साल भर में अब तक 3766 किग्रा यानी लगभग 773 लाख से भी अधिक की बरामदगी कर 25 से अधिक तस्करों को जेल भेजा चुका है। यह सब पूर्वांचल में तीन दर्जन से अधिक ईनामी माफियाओं को ढेर कर चुके तेज-तर्रार जांबाज क्राइमब्रांच इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी एवं उनकी टीम स्थानीय पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ छापामार अभियान में की है। परिणाम यह है कि इस कार्रवाई से नशे की लत में अपने लाडलों को जाने से त्रस्त न सिर्फ आमजनमानस खुश है, बल्कि प्रशासनिक अफसर भी रोज-रोज की शिकायतों से राहत महसूस कर रहे है

सुरेश गांधी

एक तरफ महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से मुंबई और आस पास के इलाकों में फैले ड्रग्स की चेन को तोड़ने के लिए लगातार कोशिश जारी है, तो दुसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश पर पूर्वांचल में न सिर्फ माफियाओं व बाहुबलियों बल्कि गाजा सहित अन्य तस्करों को चुन-चुन कर उनके असल ठेकानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस कड़ी में केवल भदोही में ही सालभर में 37.66 कुंतल गाजा, जिसकी कीमत लगभग 7.73 करोड़ से भी अधिक की बताई गयी है। इसीके साथ अब तक 25 से अधिक गाजा तस्करों को जेल भेजा चुका है। यह सब पूर्वांचल में तीन दर्जन से अधिक ईनामी माफियाओं को ढेर कर चुके तेज-तर्रार जांबाज क्राइमब्रांच इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी एवं उनकी टीम स्थानीय पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ छापामार अभियान में कर रही है। परिणाम यह है कि इस कार्रवाई से नशे की लत में अपने लाडलों को जाने से त्रस्त न सिर्फ आमजनमानस खुश है, बल्कि प्रशासनिक अफसर भी रोज-रोज की शिकायतों से राहत महसूस कर रहे है। नशे के खिलाफ लगातार मुखर रहने वाले जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल का कहना है कि इस अभियान से अब आम लोगों मे उम्मीद जगी है कि पुलिस के कड़े रुख से उनके इलाके के बच्चो और युवाओं को ड्रग्स से बचाया जा सकता हैं।

पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच के अनुसार एक करोड़ से भी अधिक जब्त गाजा उडीसा, विशाखापट्टनम, नेपाल, बिहार आदि इलाकों लाकर तस्कर भदोही,

> “ इस कड़ी में केवल भदोही में ही सालभर में 37.66 कुंतल गाजा, जिसकी कीमत लगभग 7.73 करोड़ से भी अधिक की बताई गयी है। इसीके साथ अब तक 25 से अधिक गाजा तस्करों को जेल भेजा चुका है। यह सब पूर्वांचल में तीन दर्जन से अधिक ईनामी माफियाओं को ढेर कर चुके तेज-तर्रार जांबाज क्राइमब्रांच इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी एवं उनकी टीम स्थानीय पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ छापामार अभियान में कर रही है।

मिजार्पुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित पूरे यूपी में सप्लाई करते है। ऑपरेशन के दौरान यह पता चला कि तस्कर क्षेत्रीय कारोबारियों को बेचते है और ये कारोबारी नाबालिग बच्चों और महिलाओं के जरिए स्थानीय मजदूरों, युवाओं व बुनकरों तक पहुंचाते है। इससे न सिर्फ एक बड़ा तबका इसकी गिरफ्त में आकर घर की बर्बादी का कारण बनता है बल्कि कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियों की चपेट में आ जाता है। भदोही पुलिस के मुताबिक इस मामले में क्राइमब्रांच इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी एवं उनकी टीम के साथ-साथ स्थानीय पुलिस की मदद से ताबड़तोड़ छापामार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को उड़ीसा से सस्ते दाम पर गांजा खरीदकर दिल्ली समेत यूपी के शहरों में बेचने वाले अंतरराज्यीय तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को वाराणसी-प्रयागराज मार्ग पर ऊंज थाना क्षेत्र में नवधन के पास से ट्रक में लदा 350 किलो गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। बरामद गांजे की कीमत 35 लाख रुपए आंकी गई है। जिस ट्रक से गांजा बरामद किया गया उसमें टूटे हुए शीशे लदे थे। ट्रक के केबीन में गांजे को छुपाकर रखा गया था। ये तस्कर उड़ीसा से आगरा की ओर जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक डा अनिल के मुताबिक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी और ऊंज थाना प्रभारी को इस बारे में जानकारी मिली। शनिवार सुबह पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी तभी एक ट्रक में गांजा होने की जानकारी मिली। पूछताछ और तलाशी के दौरान गांजा सहित 10 चक्का ट्रक, एक मोबाइल और 1700 रुपये नकद जब्त कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों में पवन कुमार यादव निवासी अकबर टोम थाना सिकंदरा जनपद आगरा व प्रवेंद्र सिंह निवासी नवापुरा थाना सादाबाद जिला हाथरस शामिल हैं। इस मामले में दो और आरोपियों का नाम सामने आया है, उनमें शनि यादव निवासी मथुरा व कपिल चैधरी निवासी सिकंदरा शामिल हैं। पूछताछ में पवन ने बताया कि इन लोगों का पूरा एक गैंग है। जो कि उड़ीसा निवासी कपिल चैधरी उर्फ विष्णु चैधरी उर्फ केपी भाई से सस्ते दामों पर गांजे की खेप खरीदते हैं। इसके बाद यूपी के अलग-अलग जनपदों में उसे सप्लाई करते हैं। इसी तरह 20 अगस्त को क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने हाइवे के एक ढाबे के पास से अंतरराज्यीय दो तस्करों को 5.20 कुंतल गांजा संग गिरफ्तार किया था। गांजे की कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गयी थी। इस मामले में पुलिस ने गांजा तस्कर अंकित पवार निवासी मुजीदाबाद नंगल, थाना डोगर जिला बागपत और शिवनाथ निषाद पुत्र नाहर निषाद निवासी पूरेजंतर मुसाफिरखाना जिला अमेठी को जेल भेजा था। पूछताछ में शिवनाथ ने बताया कि उसकी एक गैंग है। जिसका लीडर पलटन कुमार निवासी गाजियाबाद करता है। खरीदारी के समय वह विशाखापटनम में मौजूद रहे और उसके बाद गाजियाबाद चले गए। हम लोग माल लेकर गाजियाबाद पहुंचते और उसके बाद बताए स्थान पर पहुंचाते। नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली में गांजे को ऊंचे दाम पर बेचते।

गिरफ्तारी करने वाले टीम में स्वाट प्रभारी विनोद कुमार दूबे, सर्वेश राय, तुफैल अहमद, नागेंद्र यादव, दीपक यादव, नीरज यादव, सुनील कन्नौजिया, अखिलेश यादव को पुरस्कृत किया गया था। इसी तरह 12 सितम्बर को औराई पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने विक्रमपुर स्कूल के पास से अंतरप्रांतीय गांजा तस्कर गिरोह के सरगना सहित सात लोगों के पास से तीन लग्जरी कार और 16 किलो गांजा के अलावा 80,608 रुपये बरामद किए गए। इस मामले में क्राइम ब्रांच के प्रभारी विनोद दुबे व स्थानीय पुलिस ने प्रशांत सिंह, कुमार ऊर्फ गोलू, दिग्विजय सिंह, इरशाद अली खां, देवेंद्र सिंह, पंकज दुबे और शनि सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसी तरह 28 सितम्बर को पुलिस ने तीन तस्करों को भी गिरफ्तार कर उनके पास से कंटेनर के अंदर कार में रखा 190 किलो से अधिक गांजा बरामद किया। इसकी कीमत 17 लाख रुपए बताई गयी। इसे उड़ीसा से लाया जा रहा था और पूर्वांचल के कई जिलों में आपूर्ति होना था। इसीतरह 12 सितम्बर को जौनपुर-सीमा स्थित धौरहरा पुलिस चैकी के के पास से चार तस्करों के पास 14 सौ दस किलो गांजा बरामद किया गया था। तस्कर गाजे को एक वोल्वो बस में 42 प्लास्टिक के बोरे में रख करले जा रहे थे। इसकीकीमत डेढ़ करोड़ बतायी गयी। इसमें गांजा के साथ बस तथा दो नोकिया कीपैड मोबाइल जब्त किया गया। इसी तरह उंज बार्डर पर दो तस्करों के साथ 4 कुंतल 70 किलो गांजा बरामद किया गया। इसकी कीमत करीब 90 लाख रुपये बताई गई। कंटेनर को मोडीफाई करवा कर गांजा तस्करी के लिए लाकर बनवा रखे थे।

पकड़े गए तस्करों में कमलेश यादव पुत्र मेहीलाल यादव निवासी चकहरबंश भटान व कुशल सिंह पुत्र सूबेदार सिंह निवासी बिगहिया थाना हंडिया है। बताया गया कि सरगना दिनेश सिंह निवासी सेमराज जंगीगंज जिला भदोही का रहने वाला है। गांजा तस्करी का गैंग चलाने वाले रूपम सिंह व दिनेश सिंह ने यूपी के मीरजापुर, भदोही, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सहित अन्य जनपदों में अपना जाल फैला रखा है। पुलिस की पूछताछ में कमलेश ने बताया कि वह महीने में कम से कम चार से पांच ट्रिप माल वह उड़ीसा से लाया करता था। कंटेनर में चालक के ठीक पीछे व डाला के बीच एक बड़ी से गुप्त आलमारी बनवा रखे थे, दरवाजा चालक सीट के पीछे था। जबकि डाटा की तरफ पूरा लोहे की प्लेट लगवा कर पैकर कर रखे थे, चालक सीट हटने के बाद ही यह आलमारी खुलती थी। कंटेनर में बनवाई गई यह गोपनीय आलमारी काफी बड़ी थी, इसमें गांजा रखने के बाद दरवाजे की कुंडी में सीट के पीछे चालक कपड़ा टांग रखा था। ताकि किसी को शक न हो। इसी तरह गोपीगंज पुलिस ने पकड़े गये आरोपी के पास से एक किलो 800 ग्राम गांजा और एक अदद चोरी की बाइक संख्या-यूपी 66 वी 6188 (फैशन प्रो) काले रंग की बाइक बरामद की। आरोपी अखिल गिरी पुत्र मुंशी उर्फ. लालमणि निवासी बैजलपुर थाना हंडिया जिला प्रयागराज को जेल भेज दिया। इसीतरह भदोही पुलिस ने 386 किग्रा गाजा बरामद किया, जिसकी कीमत 4 करोड़ 50 लाख बताई गई। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें गुरप्रीत सिंह, जसराना गोबिंद नगर भतेगढ़ और जोरा सिंह, पिंड बीजा लुधियाना पंजाब शामिल हैं।

“ पुलिस अधीक्षक डा अनिल के मुताबिक क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विनोद द्विवेदी और ऊंज थाना प्रभारी को इस बारे में जानकारी मिली। शनिवार सुबह पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी तभी एक ट्रक में गांजा होने की जानकारी मिली। पूछताछ और तलाशी के दौरान गांजा सहित 10 चक्का ट्रक, एक मोबाइल और 1700 रुपये नकद जब्त कर लिया गया।

दोनों कीडनी फेल, फिर भी जरुरतमंदों की मदद की ललक

धर्म एवं आस्था की नगरी काशी में अजीत सिंह बग्गा उस सख्सियत का नाम है, जिनके समाजसेवा की ललक के आगे स्वाथ्य कोई मायने नहीं रखता। उनकी दोनों किडनी फेल है, हर तीसरे दिन डायलिसिस होती है, लेकिन सुबह से रात के दो बजे तक वे हर उस जरुरतमंद की ममद के लिए तत्पर रहते है, जो अभावग्रस्त है। चाहे वह कमजोर वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक उत्थान की बात हो या मुफलिसी की जिन्दगी जी रहे परिवारों को परिणय सूत्र में बांधने से लेकर उनके घर बसाने की, हर मसलों पर वे चट्टान की तरह तनकर खड़े रहते है। और जब व्यापारियों के उत्पीड़न की हो तो उन्हें न्याय दिलाएं बगैर चैन से नहीं बैठते। उनके जीवन में एक ऐसा भी वक्त आया जब वे दिल्ली के एक अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी कान में एक व्यापारी को हत्या के झूठे मुकदमें जेल भेजे जाने की खबर पहुंची, बनारस आ गए और मुकदमा वापस कराने के बाद ही दवा की डोज ली। कोरोनाकाल में उन्होंने कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्हें नाश्ता व भोजन मुहैया कराने के साथ झोपड़पट्टियों में रहे रहे लोगों में भोजन से लेकर कंबल तक जिस तरीके से वितरीत किया, वह समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य रहे समाजसेवियों के लिए अद्भूत मिसाल बन गया है

सुरेश गांधी

यूं तो समाजसेवा के हजारों किस्से हैं। लेकिन कुछ लोग समाजसेवा को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लेते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को अपनी दिनचर्या में शुमार कर उनके प्रति निःस्वार्थ भाव से सेवारत रहते हैं। सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि उनकी सेवा के लिए अपना सबकुछ छोड़ भी देते हैं। चाहे कितनी मुश्किलें आएं, वो अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक शख्सियत हैं वाराणसी के सिगरा स्थित गांधीनगर कालोनी निवासी अजीत सिंह बग्गा। बग्गा काशी के उन चर्चित शख्सियतों में शुमार है, जिनकी पूरी जिंदगी दुसरों की सेवा में ही बीत रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी पहचान सामाजिक कार्यों से है। वह चाहे गरीब घरों की बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराने की बात हो या व्यापारियों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्य हो या उनके उत्पीड़न से लेकर माफियाओं की वसूली से बचाना हो या गायों की सेवा हो या बंदरों को फल खिलाकर उनका पेट भरने का प्रयास। पक्षियों के ठहरने के लिए घोसलों की व्यवस्था हो या फिर उनके खाने-पीने का इंतजाम।

“गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा को अपनी दिनचर्या में शुमार कर उनके प्रति निःस्वार्थ भाव से सेवारत रहते हैं। सिर्फ सेवा ही नहीं बल्कि उनकी सेवा के लिए अपना सबकुछ छोड़ भी देते हैं। चाहे कितनी मुश्किलें आएं, वो अपनी गतिविधियों से पीछे नहीं हटते। ऐसी ही एक शख्सियत हैं वाराणसी के सिगरा स्थित गांधीनगर कालोनी निवासी अजीत सिंह बग्गा।

वह सामाजिक सरोकार की हर उस डगर की साक्षी हैं, जिस पर चलकर गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, मजलूमों का दुख-दर्द साझा किया जा सकता हो।

मतलब साफ है सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाने वाले श्री बग्गा ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर ली है। समाजसेवा का जुनून उनके सिर चढ़कर बोलता है। बग्गा वैसे तो पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव समर्पित रहते हैं, लेकिन खासतौर पर विगत तकरीबन डेढ़ वर्षो से कोरोना संक्रमण काल के दौरान उन्होंने मानव सेवा की जो अद्भुत मिसाल पेश की है, वह अनुकरणीय ही नहीं, बल्कि प्रेरणास्रोत भी बन गई है। कोरोनाकाल में बग्गा ने कोविड हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन मुहैया कराने का संकल्प लिया, जिसे अमलीजामा पहनाने के लिए वह प्रातः ही उठ जाया करते और स्वयं नाश्ता तैयार करने के साथ ही उसकी पैकिंग करके हॉस्पिटल में पहुंचाने तक, जहां उसे कोविड मरीजों को वितरित किया जाता रहा। खासकर निचले तबके के झोपड़पट्टियों में खुद जरुरतमंदों तक पहुंचकर भोजन से लेकर बच्चों के टॉफी-बिस्कुट खुद बांटते थे। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 25 लाख से भी अधिक राशि के भोजन-कंबल सहित अन्य जरुरी सामाग्रियों को जरुरतमंदों में वितरीत किया।

यही कारण है कि उनका समाजसेवा से राजनीति तक का सफर विनम्रता और जनकलण का एक बेहतरीन उदाहरण है। समाजसेवा के साथ-साथ वह राजनीति में भी सक्रिय हैं। यह अलग बात है कि भारी-भरकम तामझाम व दिखावे के मायाजाल से दूर रहने के नाते राजनीतिक पार्टियों ने उनकी पहचान व सोहरत के मुताबिक सेवा लेने की जरुरत नहीं समझी और जब मौका मिला भी तो उनके विरोधी उन्हें यह कहकर बरगलाने में सफल रहे कि वे चुनाव नहीं जीत सकते। जबकि उनके जुझारुपन को देखते हुए एक-दो नहीं बल्कि 40 साल से लगातार विभिन्न व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष चुने जाते रहे। बता दें, 25 जून 1960 को बग्गा का एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। उनकी शिक्षा-दिक्षा वाराणसी में ही हुई। 1980 में बीएचयू से ग्रेजुएशन की और पढाईकाल से ही समाजसेवा की भावना जागृत हो गयी। महामना की बगिया में दूर-दराज से आकर पढ़ने वाले हर उन छात्रों की मदद के लिए आगे बढ़ जाते, जिनकी सीनियर छात्रों द्वारा उत्पीड़न किया जाता। खासकर उनका हौसला उस वक्त देखने को मिला जब 1984 के दंगे में उनके पूरे परिवार को बंधक बना लिया गया, लेकिन उन्होंने साहस का परिचय देते हुए अशोक अग्रवाल की मदद से लाठी-डंडे व पेट्रोल से आग लगाते उपद्रवियों से बचते हुए अपने पूरिवार को सुरक्षित किया।

बिना किसी पूर्व विचार के उनकी समाज सेवा के जुनून ने उन्हें राजनीति के क्षेत्र में ला दिया। समाज सेवा में उनके प्रयासों को पहचान मिली और जवाहर नगर में ही उन्हें काशी-बिस्कुट कंफेन्सरी व्यापार संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। इस पद एवं गरिमा के अनुरुप व्यापारियों की सेवा में जुटे रहे और उनके उत्पीडन को लेकर इतना मुखर हो जाते कि अधिकारियों के बिल्ले तक नोच लेते थे। 1985 में उनका विवाह लुधियाना के लवप्रीत कौर से हो गया और पारिवारिक

जिम्मेदारियों का निवर्हन करते हुए समाज सेवा में जुटे रहे। खास बात यह है कि समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें लवप्रीत कौर का भी साथ मिलता रहा और अपने प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशल के बल पर उन्होनें अपने पति की कड़ी मेहनत और नैतिकता के साथ कंधे से कन्धा मिलाया, जिसके बाद उन्होंने कई व्यवसायों और कार्यक्षेत्रों में विस्तार किया। उनकी सक्रियता को देखते हुए उन्हें

“यही कारण है कि उनका समाजसेवा से राजनीति तक का सफर विनम्रता और जनकलण का एक बेहतरीन उदाहरण है। समाजसेवा के साथ-साथ वह राजनीति में भी सक्रिय हैं। यह अलग बात है कि भारी-भरकम तामझाम व दिखावे के मायाजाल से दूर रहने के नाते राजनीतिक पार्टियों ने उनकी पहचान व सोहरत के मुताबिक सेवा लेने की जरुरत नहीं समझी और जब मौका मिला भी तो उनके विरोधी उन्हें यह कहकर बरगलाने में सफल रहे ।

भी व्यापारी महिला मंडल संघ का अध्यक्ष चुना गया। बग्गा के लगन व प्रेम के साथ-साथ साहस की गाथा को ऐसे भी समझा जा सकता है कि लगातार 30 साल से वह किसी न किसी रुप में व्यापार संघ के महत्वपूण पदों पर बने रहे। वर्तमान में भी वह वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष है। व्यापार संघ के विभिन्न पदों रहते हुए उन्होंने जगह-जगह निःशुल्क नेत्र शिविर, वृक्षारोपण, मरीजों में फल-वितरण से लेकर भोजन व नाश्ते का प्रबंध समय-समय पर करते रहे। खासा सोहरत उस वक्त मिली जब पूरे शहर में चाइल्ड लेबर के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता रहा। लेकिन वह अधिकारियों को समझाने में सफल रहे है कि चाइल्ड लेबर के वे खुद मुखर विरोधी और जहां कहीं भी उन्हें चाइल्ड लेबर मिलते है उनके पुर्नवास का प्रबंधन वह खुद करते है। श्रीनिवास आश्रम में बालश्रमिकों को रखकर उनकी शिक्षा-दीक्षा से लेकर परवरिश तक खुद करते है।

हर तीसरे दिन होती है डायलिसिस

एक मुलाकात के दौरान बग्गा ने बताया कि साल 2015 में उन्हें हार्ट अटैक आया। इस दौरान चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें बाइपास सर्जरी करानी पड़ी। कुछ दिनों बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के मेदांता हास्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उस वक्त दोनों हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल है। स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि जानने वालों में बेचैनी बढ़ गयी, परिवार निरास होने लगा, पूरे शहर में अफवाह फैल गयी, बग्गा अब नहीं बचेंगे, लेकिन मैने हिम्मत नहीं हारी और दो सप्ताह के भीतर बाबा विश्वनाथ व वाहे गुरु की मदद से सब ठीक हो गया और लोगों के बीच में हूं। हालांकि उन्हें हर तीसरे दिन डायलिसिस करानी पड़ती है। इसी बीच उन्हें पता चला कि तेलियाबाग के एक व्यापारी को पुलिस 302 के आरोप में जेल भेज दिया है। मैं तुरंत बनारस आ गया और बेगुनाह व्यापारी को जेल से बाइज्जत रिहा कराया। एक पुरानी घटना जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2002 से 2015 तक आएं दिन माफियाओं की फिरौती के चलते व्यापारियों की हत्याएं व लूटपाट की घटनाएं होती थी। व्यापारी डरे-डरे से रहते थे। लेकिन उस दौर में भी माफियाओं की परवाह किए बगैर उनके खिलाफ अभियान चलाएं रखा। इसके लिए कभी-कभी अधिकारियों के सामने धरना-प्रदर्शन के साथ-साथ छीना-झपटी भी हो जाती थी। लेकिन मांग पूरी होने तक उटा रहता था।

लॉकडाउन में गरीबों और जरूरतमंदों की खूब की मदद

कोरोनाकाल में मरीजों को फल, दलिया हलुआ, केला, दलिया-दूध, हल्दी-दूध, पनीर, बादाम, उपमा फल, बिस्कुट आदि वितरित किया गया। हर दिन नाश्ता बदलकर दिया जाता रहा। साथ ही पौष्टिकता का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। उनका कहना है मानव एवं पशु सेवा ही माधव सेवा है। सेवा परमो धरमः को मानते हुए उनका अनवरत सेवा कार्य जारी है। उनका कहना है कि इस संकटकाल में एक-दूसरे का सहारा बनने का वक्त था। हमको कोरोना से दूरी बनाना था, समाज से नहीं। हमको हाथ नहीं मिलाना था, पर हाथ छोड़ना भी नहीं था। यही वजह रहा कि उन्होंने सिर्फ मरीजों को ही नहीं बल्कि घाट के नाविकों से लेकर संगीतकारों में भी समाजसेवा करते रहे। उन्हें खुशी है कि वह बुरा वक्त भी गुजर गया। बग्गा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को, खासकर स्लम एरिया के लोगों को भोजन की परेशानियों को देखते हुए उनके बीच जाकर निरंतर उन्हें खाद्य सामग्री मुहैया कराया। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों को हो रही अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, दवाओं का अभाव को दूर करने की हरसंभव कोशिश की। कोरोना से मृत लोगों के अंतिम संस्कार के लिए भी आवश्यक सामग्री जुटाने में वह सहयोग करते रहे। बग्गा कहते हैं कि पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने से उन्हें सुखद अनुभूति होती है। इससे मानव जीवन की सार्थकता भी साबित होती है। उनका मानना है कि अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालते हुए सामाजिक कार्यों के प्रति भी समय निकालकर लोगों को सहभागिता निभानी चाहिए। विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने से ईश्वर भी खुश होते हैं। उनका कहना है कि अगर समाजसेवा का जज्बा दिल में हो तो किसी भी तरह इंसान सेवा कर सकता है। समाजसेवा से केवल खुद को सुकून मिलता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की सहायता भी की जा सकती है। वह बचपन से ही समाजसेवा करना चाहते थे, उनको सेवा करने का जुनून था। अंत में बग्गा यह गाना गुनगुनाते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं ह्लगरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा, तुम एक पैसा दोगे, वो दस लाख देगाह्व। व्यापारी अमृत लाल कहते है लॉकडाउन के दौरान उन्होंने मानव सेवा की मिसाल तो पेश की ही, इसके अलावा उन्होंने सड़कों पर लावारिस विचरण करते बेजुबान जानवरों के लिए भी निवाले की व्यवस्था कर पशु प्रेमी होने का परिचय दिया। समाजसेवा को ही उन्होंने अपना ओढ़ना-बिछौना बना लिया है।

“एक मुलाकात के दौरान बग्गा ने बताया कि साल 2015 में उन्हें हार्ट अटैक आया। इस दौरान चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें बाइपास सर्जरी करानी पड़ी। कुछ दिनों बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के मेदांता हास्पिटल में भर्ती होना पड़ा। उस वक्त दोनों हाथ पैर काम करना बंद कर चुके थे। जांच में पता चला कि उनकी दोनों किडनी फेल है। स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि जानने वालों में बेचैनी बढ़ गयी।

व्यापारियों की हर समस्या के लिए करेंगे संघर्ष

बग्गा ने कहा कि व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के निदान के लिए संघर्ष किया जाएगा। चाहे वाणिज्यकर विभाग की सचल दल हो या अन्य इकाइयां व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगी। अधिकारियों को मनमानी नहीं करने दी जायेगी। व्यापारी समाज ही 80 प्रतिशत लोगों को नौकरी देता है। युवा व्यापारियों को जोड़कर व्यापारियों की समस्याओं पर मौके पर तत्परता से पहुंचने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। उनका संघ व्यापारियों की समस्याओं को लेकर निरंतर संघर्ष कर रहा है और करता रहेगा। किसी भी दशा में व्यापारियों का अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न नही होने दिया जाएगा। साथ ही साथ सरकार से मांग है कि व्यापारियों को 10 लाख रुपये को बीमा दिया जाए और अधिकारियों के भांति ही व्यापारियों को 60 से 65 वर्ष की अवस्था में कर्मचारियों की भांति पेंशन दिया जाए ताकि बुजुर्ग व्यापारी अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। व्यापारियों के साथ किसी भी तरह का जुल्म व अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। व्यापारियों के हितों की रक्षा लिए संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। संगठन शक्ति का प्रतीक है। संगठित रहकर व्यापारी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकेगा।

> बग्गा ने कहा कि व्यापारियों की हर समस्या के समाधान के निदान के लिए संघर्ष किया जाएगा। चाहे वाणिज्यकर विभाग की सचल दल हो या अन्य इकाइयां व्यापारियों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। अधिकारियों को मनमानी नहीं करने दी जायेगी। व्यापारी समाज ही 80 प्रतिशत लोगों को नौकरी देता है। युवा व्यापारियों को जोड़कर व्यापारियों की समस्याओं पर मौके पर तत्परता से पहुंचने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी।

उल्कापिंड को जोरदार टक्कर देने के लिए फाल्कन राकेट को नासा ने अंतरिक्ष में किया रवाना

जितेन्द्र कुमार सिन्हा, पटना

नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड (एस्टेरायड) के हमलों से बचाने के लिए फाल्कन राकेट को अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के लिए रवाना कर दिया है। नासा का इस तरह का यह पहला मिशन है। अगर नासा को इस मिशन में सफलता मिलती है, तो भविष्य में उन विशाल उल्कापिंडों को धरती पर आने से पहले ही रोका जा सकेगा। उल्कापिंड जब धरती से टकरायेगा तो यहां के जीवन के लिए खतरा बन सकता है। नासा के वैज्ञानिक यह देखना चाहते हैं कि डिमोफोर्स की गति से और रास्ते को कितना बदला जा सकता है। हालांकि, डिमोफोर्स से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। यह भविष्य में पृथ्वी की ओर आने वाले ऐसे खतरों से निपटने का तरीका सीखने का पहला प्रयास है, यानि भविष्य में कोई ऐसा पिंड या मलवा धरती की ओर आता है, तो उसे कैसे दूर रखा जा सकता है। 24 नवम्बर, 2021 को फाल्कन 9 राकेट, डार्ट अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के वेंडेबर्ग स्पेस फोर्स बसे से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया है।

उल्कापिंड, सौर मंडल के बचे हुए खंड हैं, जिनमें से अधिकांश से पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं होता, लेकिन जब ऐसी कोई चट्टान सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ती, तो टक्कर की आशंका हो सकती है। 32 करोड़ अमेरिकी डॉलर लागत का डार्ट मिशन, उल्कापिंड की जोड़ी को निशाना बनाएगा, जो इस वक्त एक-दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसी परिक्रमा को बाइनरी कहा जाता है। इन दोनों में से बड़े उल्कापिंड का नाम है डिडिमोस, जो करीब 780 मीटर में फैला है। डिमोफोर्स करीब 160 मीटर चौड़ा है। पिछले कई सालों से वेन्नू नाम के एक उल्कापिंड की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। कहा जाता रहा है कि आने वाले सालों में यह पृथ्वी से टकरा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर कब पृथ्वी से इसकी टक्कर होगी, इसको लेकर लोगों द्वारा तरह-तरह के अंदाज लगाए जा रहे है। लेकिन इसी बीच नासा ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया है। नासा के अनुसार वेन्नू के धरती से टकराने का आशंका बहुत ही कम है। अगर ऐसा हुआ तो इसकी टक्कर 24 सितम्बर, 2182 को हो सकती है। वेन्नू की पृथ्वी से टकराने की आषंका पहले से ज्यादा है, लेकिन वैज्ञानिक अब इसको लेकर चिंतित नहीं है, पहले बेन्नू को लेकर काफी चिंतित था, लेकिन जब नासा ने एस्टरायड पर अंतरिक्ष यान भेजा है तबसे वे अब चिंतीत नहीं है।

ओसिरिस आरइक्स के इस अंतरिक्ष यान को 2018 में भेजा गया था। 2020 के अंत में उल्कापिंड की सतह पर यह सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा और इसके बाद इस यान ने नमूने भेजने शुरू कर दिया। अंतरिक्ष यान ने बताया कि बेन्नू एक बहुत ही डार्क और प्राचीन उल्कापिंड है। नासा के एक ब्यान में कहा गया है कि बेन्नू की सतह से नमूने जमा कर अंतरिक्ष यान ने भेजा है, जिससे बेहतर भविष्यवाणी करने के लिए सटीक आंकड़ा मिल रहा है। करीब साढ़े चार अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल, जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाया और पीछे छूट गया, वही इन चट्टानों में यानि उल्कापिंडों में तब्दील हो गया है। यही कारण है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता।

> “नासा ने अंतरिक्ष में मौजूद एक उल्कापिंड (एस्टेरायड) के हमलों से बचाने के लिए फाल्कन राकेट को अंतरिक्ष में अपने अंतरिक्ष यान से जोरदार टक्कर कराने के लिए रवाना कर दिया है। नासा का इस तरह का यह पहला मिशन है। अगर नासा को इस मिशन में सफलता मिलती है, तो भविष्य में उन विशाल उल्कापिंडों को धरती पर आने से पहले ही रोका जा सकेगा। उल्कापिंड जब धरती से टकरायेगा तो यहां के जीवन के लिए खतरा बन सकता है।

बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, के पटना 103वें स्थापना दिवस वर्षगांठ संपन्न

देश में हिन्दी के विकास में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अभूतपूर्व योगदान

साहित्य ही मानव को मनुष्य बना सकता है

देशरत्न डा . राजेंद्र प्रसाद भी हिन्दी प्रचारकों में शामिल थें : अश्विनी चौबे

बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन पटना बिहार के १०३वें स्थापना दिवस पर २५ विदुषियों और विद्वानों का हुआ सम्मान,

पूनम आनंद के लघुकथा संग्रह 'कौफी टाइम्स' का भी हुआ लोकार्पण

बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता

हिन्दी भाषा और साहित्य के उन्नयन में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन का महान अवदान हमें गौरवान्वित करता है। पूरे भारतवर्ष में हिन्दी भाषा के प्रचार में इसका योगदान अभूतपूर्व है। बिहार के महान हिन्दी साहित्यकारों के साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डा. राजेंद्र प्रसाद और बाबू गंगा शरण सिंह जैसे देश के महान नेता भी सम्मेलन के हिन्दी प्रचारकों में सम्मिलित थें।

उपर्युक्त बातें सम्मेलन के १०३वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए, भारत के खाद्य, वन और पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कही। उन्होंने कहा कि देश की जिन साहित्यिक विभूतियों और हिन्दी-प्रेमियों ने इसके चतुर्दिक प्रचार और उन्नति के लिए मूल्यवान कार्य किए, उनमें बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन से जुड़े महान साहित्यकारों का योगदान अत्यंत महनीय है। हिन्दी की इस महान सेवा के लिए, हमें भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डा राजेंद्र प्रसाद जी, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर', महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, आचार्य रामवृक्ष बेनीपुरी, डा काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू गंगा शरण सिंह , श्री भवानी दयाल सन्यासी, महाकवि रामदयाल पाण्डेय आदि महापुरुषों का श्रद्धा से स्मरण होता है, जो अलग-अलग समय में बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे।

श्री चौबे ने कहा कि समाज में गुणात्मक परिवर्तन साहित्य के द्वारा हीं संभव होता है। साहित्य हीं मानव को 'मनुष्य' बना सकता है। इसके अभाव में मनुष्य, मनुष्यता से दूर, संस्कार-हीन और असामाजिक हो जाता है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस संकल्प का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि देश की अपनी 'एक राष्ट्र-भाषा' अवश्य होनी चाहिए और वह 'हिन्दी' ही हो सकती है। इसमें

> “सम्मेलन के १०३वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए, भारत के खाद्य, वन और पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कही। उन्होंने कहा कि देश की जिन साहित्यिक विभूतियों और हिन्दी-प्रेमियों ने इसके चतुर्दिक प्रचार और उन्नति के लिए मूल्यवान कार्य किए, उनमें बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन से जुड़े महान साहित्यकारों का योगदान अत्यंत महनीय है।

सहायक होकर हमें प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति होगी।

इस अवसर पर श्री चौबे ने कुल २५विदुषियों और विद्वानों को 'साहित्य-मार्तण्ड', साहित्य-चूड़ामणि' और 'साहित्य-शार्दूल' अलंकरणों से सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने, विदुषी लेखिका पूनम आनंद के लघुकथा-संग्रह'कौफी टाइम्स' का लोकार्पण किया। उपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि साहित्य सम्मेलन ने केवल हिन्दी साहित्य का ही संवर्द्धन नहीं किया अपितु स्वतंत्रता-आंदोलन में भी इसकी बड़ी भागीदारी हुई। जैसा त्याग और बलिदान स्वतंत्रता सेनानियों का है, वही त्याग और बलिदान हिन्दी के साहित्यकारों का हैं। यह सम्मेलन एक साहित्यिक-तीर्थ सा स्थान रखता रहा है।

आरंभ में अतिथियों का स्वागत करते हुए, स्वागत समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. सीपी ठाकुर ने माननीय मंत्री से आग्रह किया कि वे साहित्य सम्मेलन के संकल्प को पूरा करने हेतु भारत के प्रधानमंत्री के सामने हमारा वकील बनें।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में, सम्मेलन अध्यक्ष डा. अनिल सुलभ ने सम्मेलन के १०२ वर्षों के गौरवशाली इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि बहुत विलंब हो चुका, अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज की भाँति हिन्दी को देश की 'राष्ट्रभाषा' घोषित की जाए।

बिहार के पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) आलोक राज, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार के पूर्व अध्यक्ष प्रो. शशिशेखर तिवारी, पटना विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति डा. एस एन पी सिन्हा तथा मधेपुरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. अमरनाथ सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन सम्मेलन के उपाध्यक्ष डा शंकर प्रसाद और साहित्यमंत्री डा. भूपेन्द्र कलसी ने तथा धन्यवाद-ज्ञापन प्रधानमंत्री डा शिववंश पाण्डेय ने किया।

उद्घाटन-सत्र के पश्चात सम्मेलन के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ कवि मृत्युंजय मिश्र 'करुणेश' की अध्यक्षता तथा संचालक विजय गुंजन में एक भव्य कवि-सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों और बिहार के ४० से अधिक कवियों ने अपना काव्य-पाठ किया।

कवि संजय पंकज मुजफ्फरपुर बिहार ने भारतीय औरत का बड़ी खूबसूरत अंदाज से सटीक आकलन किया-

" गणित का हिसाब रखती औरत / जोड़ , गुणा
औरों के लिए/ अपने लिए घटाव हो
होती है औरत ...."

डॉक्टर कल्याणी कबीर का कहना है-

" बात बेवाक न लिखें तो कलम बंद रखिए/ नजर अंदाज करके, तेरे मेरे जलते घर /आग को आग न लिखें तो/ कलम बंद रखिए ।.... "

बिंदेश्वर प्रसाद गुप्ता ने धर्म की विसंगतियों के खिलाफ आवाज उठाई-.....

" यह कैसा धर्म है ./ जिसकी कोख से/ जन्म लेता है / संप्रदायवाद , अराजकता / विषमता और आतंकवाद..."

प्रतिभा स्मृति जी का कहना था - " बात परायी का क्या कहना , अपनों ने नहीं जाना..." , वहीं डा. अनीता शर्मा जमशेदपुर ने- " बेटी ! रिश्तों का गणित आज समझाऊँ क्या ? ....." कहती हुई अपने अंतर्वेदना से मर्माहत कर दिया । डॉ. रजनी शर्मा ' चंदा ' रांची ने श्रृंगारिक कविता सुनायी- "धीरे-धीरे से बहना / ओ री पवन /नदिया किनारे होगा मिलन ...." डॉक्टर

अलका वर्मा, सुपौल को अपने वजूद की चिंता काफी सताती है - " मुझे मेरे नाम से पुकारो ,... मैं अपना वजूद चाहती हूँ / मुझे मेरा वजूद लौटा दो ...।

...."

कौशर कोलहुवा कमालपुरी ने अपने ' ' देशप्रेम ' का जज्बा से लोगों को

परिचित कराया-

" सबसे प्यारा नयन का तारा यह अवनि कंठहार / युग- युग जियो, स्वतंत्र भारत नमन हजारों हजार..."

डॉ. मीना परिहार ने अपना अनुभव सुनाया - " बहुत तंग दिल है दुनिया, छोड़ देती है..." डॉक्टर प्रतिभा पाराशर ने शरद पूर्णिमा के अवसर पर गीत सुनाया - " शरद चंदनिया मिली, चितवन हुआ चकोर ...." तथा

." ... तुम्हीं ने बसाया शहर को / ..... सुनो कृष्णा आओ हमारे नगर में / चलो आज प्रतिभा , नजारे बदल दे / चमकते नहीं सब सितारे , गगन में ...."

सिद्धेश्वर कश्यप ने सकारात्मक जिंदगी से एहसास कराया - " जिंदगी से प्यार करते हम / इसीलिए गुलजार करते हम....."

डॉक्टर कल्याणी जमशेदपुर ने - माँ भारती की जय करें / शत्रु के दर को क्षय करें.... डॉक्टर राजमणि राय ने अपनी कविता में अपने गाँव की दुर्दशा को बताया - " घर के छज्जे पर बोलेगा /चीं चीं करती गाय और गुटर गूँ बोलेगा कबूतर / यही है गाँव हमारा /कि ऐसा है गाँव हमारा ..."।

डॉ. महेश राय ने कोरोना से सचेत होने के लिये संदेश दिया - ' अरी यह विकराल है/ मानव का यह काल है.."।

संचालक विजय गुंजन जी ने अपनी अन्तर्वेदना से इस प्रकार इजहार किया-

-" कितने मित्र बदलते देखे/ इस बदनाम नगर में ..."

कवि सम्मेलन के अध्यक्ष मृत्युंजय झा 'करुणेश' ने गजल के माध्यम से बताया-

".... खुल जाये कभी राग, अभी ठीक नहीं है
यह साज की आवाज, अभी ठीक नहीं है...."।

...अन्य कवियों-कवयित्रियों काव्य-पाठ करने वालों में थें - चर्चित कवि मनीष मधुकर, आराधना प्रसाद, डा. जंग बहादुर पाण्डेय, कौसर 'शमा', अनिता मिश्र सिद्धि, शुभ चंद्र सिन्हा, ऋतु प्रज्ञा, अर्चना भारद्वाज , मौसमी सिन्हा, नूतन सिन्हा, डा. महेश , अभिलाषा कुमारी, मोईन गिरीडीहवी, प्रियेश सिंह, नंदन मिश्र, राम सिंगार 'मलक', अंकेश कुमार, शंकर शरण आर्य, कमल किशोर वर्मा

अपने अध्यक्षीय संबोधन में, सम्मेलन अध्यक्ष डा. अनिल सुलभ ने सम्मेलन के १०२ वर्षों के गौरवशाली इतिहास का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि बहुत विलंब हो चुका, अब भारत के राष्ट्रीय ध्वज की भाँति हिन्दी को देश की 'राष्ट्रभाषा' घोषित की जाए। बिहार के पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) आलोक राज, विश्वविद्यालय सेवा आयोग, बिहार के पूर्व अध्यक्ष प्रो. शशिशेखर तिवारी, पटना विश्व विद्यालय के पूर्व कुलपति डा. एस एन पी सिन्हा तथा मधेपुरा विविके पूर्व कुलपति प्रो. अमरनाथ सिन्हा ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

'कमल', महेश राय, जितेंद्र मिश्र, मंजू शुक्ला, रजनी श्रीवास्तव, लता परासर, राज किशोर वत्स, राजीव शर्मा आदि। ....

समारोह के अंत में, सम्मेलन के कला-विभाग की ओर से, कलामंत्री डा. पल्लवी विश्वास और पं. अविनय काशी नाथ पाण्डेय के निर्देशन में, कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर रचित और पं. हंस कुमार तिवारी द्वारा अनूदित नृत्य-नाटिका 'श्यामा' की चित्ताकर्षक प्रस्तुति की गई। भाग लेने वाले कलाकारों में आयुर्मान यास्क, रविचंद्र 'पासवाँ', रौशन महाराज, शशिकांत शर्मा, गायत्री ऋतिका, काशिका पाण्डेय, कविता तथा गुड्डी की प्रस्तुति को एक स्मृति के रूप में लेकर सुधी श्रोता विदा हुए। ....

इस अवसर पर, सम्मेलन के उपाध्यक्ष नृपेंद्रनाथ गुप्त, डा. कल्याणी कुसुम सिंह, अभिजीत कश्यप, प्रो. बासुकी नाथ झा, सुनील कुमार दूबे, बिन्देश्वर प्रसाद गुप्ता , डॉ. प्रतिभा परासर , कृष्णरंजन सिंह, डा. शलिनी पाण्डेय, डा. पुष्पा जमुआर, डा. नागेश्वर प्रसाद यादव, जय प्रकाश पुजारी, कुमार अनुपम, संजीव कुमार मिश्र, डा. मेहता नगेंद्र सिंह ,कुमारी क्रांति , डा .अर्चना त्रिपाठी, डॉ. नम्रता समेत बड़ी संख्या में सम्मेलन के सदस्य एवं साहित्यकार उपस्थित थें। इस अवसर पर जिन विद्वानों एवं विदुषियों को सम्मानित किया गया वे थें-

साहित्य मार्तण्ड --प्रो. महेन्द्र मधुकर ,प्रो सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह कश्यपडा. शंकरमुनि रायश्री ,बाबू लाल मधुकर ,डा. सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, राजमणि मिश्र , कृष्ण चंद्र दूबे।साहित्य चूड़ामणि -डा. पुष्पा रानी , डा. कल्याणी कबीर , डा. अनिता शर्मा , किरण सिंह, पूनम आनंद ,डा. शहनाज फातमी , डा. रीभा तिवारी , डा. संजू कुमारी ,डा. ममता मिश्र , श्रीमती सरिता कुमारी, मेरी आडलीन -साहित्य शार्दूल --डा. सत्य नारायण उपाध्याय, डा. संजय पंकज , डा. दिनेश कुमार शर्मा , हरिवंश प्रभात , पंकज कुमार वसंत, पं.बाल कृष्ण उपाध्याय, विनोद सिंह गहरवाल।

“साहित्य मार्तण्ड --प्रो. महेन्द्र मधुकर ,प्रो सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह कश्यपडा. शंकरमुनि रायश्री ,बाबू लाल मधुकर ,डा. सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, राजमणि मिश्र , कृष्ण चंद्र दूबे।साहित्य चूड़ामणि -डा. पुष्पा रानी , डा. कल्याणी कबीर , डा. अनिता शर्मा , किरण सिंह, पूनम आनंद ,डा. शहनाज फातमी , डा. रीभा तिवारी , डा. संजू कुमारी ,डा. ममता मिश्र , श्रीमती सरिता कुमारी, मेरी आडलीन -साहित्य शार्दूल डा. सत्य नारायण उपाध्याय, डा. संजय पंकज , डा. दिनेश कुमार शर्मा , हरिवंश प्रभात , पंकज कुमार वसंत, पं.बाल कृष्ण उपाध्याय, विनोद सिंह गहरवाल।

महिलाओं पर सवाल उठाने से पहले स्वयं में झांकने की जरूरत

एक तरफ हम चांद और मंगल पर जीवन बसाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ हमारे समाज का एक बड़ा तबका महिलाओं के ह्यड्रेसकोडह्ल में ही उलझा हुआ है। अब हम इक्कीसवीं सदी में भले पहुँच गए हो, लेकिन महिलाओं के कपड़ो को लेकर राजनीति आम हो चली है और हो भी क्यों न? आधुनिकता की दौड़ में हमारे संस्कारों की परिभाषा जो बदल गई है। ऐसे में सोचने वाली बात तो यह है कि क्या हमारी संस्कृति इतनी कमजोर है जिसे अब कपडों से परिभाषित करना पड़ रहा है? क्या अब वस्त्र ही हमारे सभ्य और असभ्य होने की परिधि तय करेंगे? मान लीजिए किसी के पति या पिता की मौत हुई है। तो क्या पहले वह ड्रेस पर ध्यान केंद्रित करें या उससे भी कोई जरूरी बात होती है। यह तो समाज को स्वयं तय करना चाहिए। ऐसा कहने के पीछे कारण है। बीते दिनों मंदिरा बेदी के पति का असमय निधन हो गया। जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया जाने लगा कि उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने फलाँ-फलां बातें हुईं।

अब सवाल यहीं क्या कोई महिला जिसके पति का निधन हुआ। वह पहले उस कपड़ें पर ध्यान केंद्रित करें या फिर पति के जाने का गम मनाएं? यह काफी साधारण सी बात है कि कोई भी व्यक्ति पहले से तो ऐसे दुःखद समय के लिए तैयार नहीं रहता। फिर ऐसे अजीबोगरीब सवाल से किसी की आत्मा और हमारे संस्कारों को औछा आखिर क्यों साबित करना। जिसपर आज के दौर में हमारे समाज को बोलना चाहिए। उन विषयों पर तो हम येन-केन प्रकारेण चुप्पी साध लेते हैं और जिन विषयों पर नहीं बोलना। उस पर बेवजह बोलकर हम बात का बतंगड़ बनाते। यह हमारे समाज में बड़ी ही अचरज वाली स्थिति निर्मित होती जा रही है। मंदिरा बेदी को पति के निधन के बाद कैसे कपड़े पहनने चाहिए या नहीं। क्या उन्हें उत्तरप्रदेश में हुई वह घटना याद नहीं आई। जब योगीराज में एक महिला प्रस्तावक के दामन को तार-तार करने वाली घटना घटित हुई? मतलब नजरिए की भी हद्द होती है। अब हमारा समाज सलेक्टिव होते जा रहा है। उसे कब, क्या और कहां कितना बोलना है। वह उतना ही करता है। फिर वह गलत, सही को भूला देता है। जो कहीं न कहीं हमारे समाज को गलत दिशा की और लेकर जा रहा है।

एक तरफ हमारे समाज में महिलाओं का संस्कारी होना उनके कपडों के आधार पर तय किया जाता है। वहीं दूसरी ओर समाज के एक वर्ग विशेष के द्वारा महिला का ही सरेआम पल्लू खींचा जाता है। वह भी उस समय जब वह महिला अपने ब्लाक प्रमुख की उम्मीदवारी का पर्चा भरने के लिए जा रही होती है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं। लेकिन उनपर गहन मंथन करने वाला कोई नहीं। हमारे देश में हाल ही में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को शामिल किया गया है। उत्तरप्रदेश सूबे की ही बात करे। तो यहां से 4 महिलाएं मोदी मंत्रिमंडल में शामिल है और 11 महिला सांसद है। इसके अलावा सूबे में 40 महिला विधायक हैं। इन सबके बावजूद एक महिला का सूबे में सरेआम पल्लू खींचा

“अब सवाल यहीं क्या कोई महिला जिसके पति का निधन हुआ। वह पहले उस कपड़ें पर ध्यान केंद्रित करें या फिर पति के जाने का गम मनाएं? यह काफी साधारण सी बात है कि कोई भी व्यक्ति पहले से तो ऐसे दुःखद समय के लिए तैयार नहीं रहता। फिर ऐसे अजीबोगरीब सवाल से किसी की आत्मा और हमारे संस्कारों को औछा आखिर क्यों साबित करना।

जाता है। वह भी तमाम मीडिया कैमरों के सामने, लेकिन सामान्य जनमानस तो सामान्य कोई भी महिला मंत्री इस मुद्दे पर अपनी आवाज तक नही उठा पाती है। कोई महिला आयोग इस मुद्दे पर खुलकर सामने नही आता है। फिर आखिर हम किस संस्कार और संस्कृति की ढपली पीटते हैं और किस हैसियत से मंदिरा बेदी को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए था या नहीं उस बात के लिए सलाह देते हैं।

मतलब लोकतांत्रिक निर्लज्जता की भी हद्द होती है। एक तरफ तो जो महिला कपड़ें पहने हुए है। उसके बदन से कपड़े खींचे जाते हैं और दूसरी तरफ एक अन्य महिला जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिसने असमय अपने पति को खो दिया। उसे कैसे कपडे पहनने चाहिए और कैसे नहीं उसकी सीख दी जा रही। वैसे कई बार जिन महिलाओं को हम अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते है वे भी मौन धारण कर लेती है। फिर काफी खीझ छूटती है, कि अगर वो ही अपने जैसी महिलाओं की बात नहीं रख सकती। फिर बाकी से क्या उम्मीद लगाई जाएं। आज के समय का एक कड़वा सच तो यह भी है कि हम जिन महिलाओं को अपने प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते है वह भी हमें इंसाफ नही दिला पाती है।

समाज का कोई भी वर्ग हो महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हर परिस्थिति में होता रहा है। महाभारत काल की ही बात करे तो द्रोपदी का चीरहरण भरी सभा मे किया गया और सारा हस्तिनापुर मौन रहा। ऐसे में आज की परिस्थितियों को देखकर यही प्रतीत होता है। मानो एक बार फिर देश महिलाओं पर होते अत्याचार के खिलाफ आंखे बंद करके तमाशबीन बन गया है।

समाज मे महिलाओं को बराबरी के हक दिए जाने की बात का ढिंढोरा बड़े जोरो शोरों से गूंजता है लेकिन जब वही महिला अपनी रूढ़िवादी परम्पराओं से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो बड़ी आसानी से उन पर लांछन लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में मंदिरा वेदी के पति की मौत पर कंधा देना और जीन्स पहनकर उनके पति का अंतिम संस्कार करने की ही घटना को देखे तो साफ दिखाई देता है कि कैसे जब कोई महिला समाज के नियमों से बाहर जाती है। तो पितृसत्तात्मक मानसिकता उन पर सवाल खड़े कर देती है। यहां सोचने वाली बात यह है कि क्या महिला के दर्द को उनके कपड़ों के आधार पर देखा जाएगा? क्या मंदिरा बेदी साड़ी पहनकर अपने पति का अंतिम संस्कार करती तो उनका दर्द बेहतर ठंग से दिखाई देता है? या फिर क्या साड़ी पहनने से मंदिरा बेदी के पति वापस लौट आते?

क्या इन सवालों के जवाब आम लोगों के आप हैं, नहीं न! फिर उस समाज के लिए एक ही बात कि वह इतना भी असंवेदनशील न हो जाएं, कि महिला को अपने महिला होने से ही दिक़्कत हो जाएं। वैसे भी वह महिला ही है। जो मां के रूप में ममता बरसाती है। वरना वह दुर्गा और काली भी बन जाती है। कुल-मिलाकर देखें तो समाज को सलेक्टिव अप्रोच से बाहर निकलना होगा। खासकर महिलाओं को लेकर।

इसके अलावा हर महिला को एक दृष्टिकोण से देखना होगा। महिला कोई भी हो, अमीर या गरीब घर की। हर महिला का सम्मान होना चाहिए। कपड़ें हमारी पहचान नहीं बन सकते, पहचान हमारा अपना व्यक्तित्व ही होता है। भले ही वह अच्छा हो या बुरा। ऐसे में व्यक्ति को चाहें वह महिला हो या पुरुष उसे अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देना चाहिए और गलत को गलत और सही को सही कहने की क्षमता हर किसी में होना चाहिए, न कि चुप्पी साधने का गुण। जैसा कि उत्तर प्रदेश में महिला के पल्लू खींचें जाने पर देखने को मिला।

आखिर में एक बात यही कि हमारे देश की तो सदियों से नारी को पूजने की परंपरा रही है। फिर क्यों आज नारी की अस्मिता पर चोट करने से समाज पीछे नही हटता? देखा जाए तो धर्म के ठेकेदारों ने ही धर्म को अपनी सुविधानुसार व्याख्या करना शुरू कर दिया है। जिसकी वजह से ये जड़तामूल्क समस्याएं उत्पन्न हो रही। जिसका निदान बहुत आवश्यक है।

“समाज मे महिलाओं को बराबरी के हक दिए जाने की बात का ढिंढोरा बड़े जोरो शोरों से गूंजता है लेकिन जब वही महिला अपनी रूढ़िवादी परम्पराओं से बाहर निकलने का प्रयास करती है। तो बड़ी आसानी से उन पर लांछन लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में मंदिरा वेदी के पति की मौत पर कंधा देना और जीन्स पहनकर उनके पति का अंतिम संस्कार करने की ही घटना को देखे तो साफ दिखाई देता है कि कैसे जब कोई महिला समाज के नियमों से बाहर जाती है।

इन महिलाओं की रही थी भारतीय संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी

भारत में 26 नवंबर 1949 को निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। लेकिन अब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कि संविधान निर्माण के संदर्भ में हमें केवल अग्रणी पुरुष सदस्यों के रूप में डॉ बी आर अम्बेडकर ही याद है, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में मदद की थी। यों तो हम जल्दी अपने इतिहास को नहीं भूलते है, पर जब हमारी सोच में पितृसत्ता का चश्मा होतो अक्सर हमारी नजरों से आधी आबादी के पूरे पन्ने ओझल से हो जाते है।शायद यही वजह है कि संविधान सभा में हम उन प्रमुख पंद्रह महिला सदस्यों का योगदान आसानी से भुला चुके है या यों कहें कि हमने कभी इसे याद करने या तलाशने की जहमत नहीं की।तो आइये जानते है उन पन्द्रह भारतीय महिलाओं के बारे में जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है

अम्मू स्वामीनाथन

अम्मू स्वामीनाथन का जन्म केरल के पालघाट जिले के अनाकारा में ऊपरी जाति के हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 1917 में मद्रास में एनी बेसेंट, मार्गरेट, मालथी पटवर्धन, श्रीमती दादाभाय और श्रीमती अंबुजमल के साथ महिला भारत संघ का गठन किया। वह साल 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बन गईं। 24 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को पारित करने के लिए डॉ बी आर अम्बेडकर ने एक चर्चा के दौरान भाषण में आशावादी और आत्मविश्वासी अम्मू ने कहा कि ह्यबाहर के लोग कह रहे हैं कि भारत ने अपनी महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं दिए हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब भारतीय लोग स्वयं अपने संविधान को तैयार करते हैं तो उन्होंने देश के हर दूसरे नागरिक के बराबर महिलाओं को अधिकार दिए हैं।ह्य वह साल 1952 में लोकसभा के लिए और साल 1954 में राज्यसभा के लिए चुनी गयी। उन्होंने भारत स्काउट्स एंड गाइड (1960-65) और सेंसर बोर्ड की भी अध्यक्षता की।

दक्षिणानी वेलायुद्ध

दक्षिणानी वेलायुद्ध का जन्म 4 जुलाई 1912 को कोचीन में बोल्गाटी द्वीप पर हुआ था। वह शोषित वर्गों की नेता थी। साल 1945 में, दक्षिणानी को कोचीन विधान परिषद में राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया था। वह साल 1946 में संविधान सभा के लिए चुनी गयी पहली और एकमात्र दलित महिला थीं।

बेगम एजाज रसूल

बेगम एजाज रसूल मालरकोटला के रियासत परिवार में पैदा हुई और उनकी शादी युवा भूमि मालिक नवाब अजाज रसूल से हुई थी। वह संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। साल 1950 में, भारत में मुस्लिम लीग भंग होने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गयी। वह साल 1952 में राज्यसभा के लिए चुनी गयी थी और साल 1969 से साल 1990 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य रही। साथ ही, साल 1969 से साल 1971 के बीच, वह सामाजिक कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री भी रही। इसके बाद साल 2000 में, उन्हें सामाजिक कार्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था।

दुगार्बाई देशमुख

दुगार्बाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को राजमुंदरी में हुआ था। बारह वर्ष की उम्र में उन्होंने गैर-सहभागिता आंदोलन में भाग लिया और आंध्र केसरी टी प्रकाशन के साथ उन्होंने मई 1930 में मद्रास शहर में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। साल 1936 में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की, जो एक दशक के अंदर मद्रास शहर में शिक्षा और सामाजिक कल्याण का एक महान संस्थान बन गया। वह केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय समिति पर लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा जैसे कई केंद्रीय संगठनों की अध्यक्ष थीं। वह संसद और योजना आयोग की सदस्य भी थी। वह आंध्र एजुकेशनल सोसाइटी (नई दिल्ली) से भी जुड़ी थीं। इसके बाद, साल 1971 में भारत में साक्षरता के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दुगार्बाई को चौथे नेहरू साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 1975 में, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।

हंसा जिवराज मेहता

हंसा का जन्म 3 जुलाई 1897 को बड़ौदा के रहने वाले मनुभाई नंदशंकर मेहता के यहाँ हुआ था। हंसा ने इंग्लैंड में पत्रकारिता और समाजशास्त्र का अध्ययन किया। एक सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ-साथ वह एक शिक्षिका और लेखिका भी थीं। उन्होंने गुजराती में बच्चों के लिए कई किताबें लिखीं और गुलिवर ट्रेवल्स समेत कई अंग्रेजी कहानियों का भी अनुवाद किया।

वह साल 1926 में बॉम्बे स्कूल कमेटी के लिए चुनी गयी और साल 1945-46 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। हैदराबाद में आयोजित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में उनके राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का चार्टर प्रस्तावित किया।

कमला चौधरी

कमला चौधरी का जन्म लखनऊ के समृद्ध परिवार में हुआ था। शाही सरकार के लिए अपने परिवार की निष्ठा से दूर जाने से वह राष्ट्रवादियों में शामिल हो गई और साल 1930 में गांधी द्वारा शुरू की गई नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भी उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लिया।वह अपने पचासवें सत्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष थी और सत्तर के उत्तरार्ध में लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गयी थी। कमला भी एक प्रसिद्ध कथा लेखिका थी और उनकी कहानियां आमतौर पर महिलाओं की आंतरिक दुनिया या आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत के उद्भव से निपटाती थीं।

लीला रॉय

लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। उन्होंने साल 1921 में बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सभी बंगाल महिला उत्पीड़न समिति की सहायक सचिव बनी और महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए मीटिंग की व्यवस्था की। साल 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना की जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बन गए, जिसमें उल्लेखनीय नेताओं ने भाग लिया।

मालती चौधरी

मालती चौधरी का जन्म साल 1904 में पूर्वी बंगाल (अब बांग्लादेश) में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। साल 1921 में, सोलह साल की उम्र में मालती चौधरी को शांति-निकेतन भेजा गया, जहां उन्हें विश्व भारती में भर्ती कराया गया। उन्होंने नाबकृष्ण चौधरी से विवाह किया, जो बाद में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने और साल 1927 में ओडिशा चले गए। नमक सत्याग्रह के दौरान, मालाती चौधरी और उनके पति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्याग्रह के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए लोगों के साथ संवाद किया।

पूर्णिमा बनर्जी

पूर्णिमा बनर्जी इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की सचिव थी। वह उत्तर प्रदेश की महिलाओं के एक कट्टरपंथी नेटवर्क में से थी जो साल 1930 के दशक के अंत में वे स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थीं। उन्हें सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी के लिए गिरफ्तार किया गया था। शहर समिति के सचिव के रूप में वह ट्रेड यूनियनों, किसान मीटिंग्स और अधिक ग्रामीण जुड़ाव की दिशा में काम करने और संगठित करने का दायित्व भी उनके ऊपर था

राजकुमारी अमृत कौर

अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में हुआ था। वह कपूरथला के पूर्व महाराजा के पुत्र हरनाम सिंह की बेटी थी।उन्हें इंग्लैंड के डोरसेट में शेरबोर्न स्कूल फॉर गर्ल्स में शिक्षित किया गया था।वह महिलाओं की शिक्षा व खेल में उनकी भागीदारी और उनकी स्वास्थ्य देखभाल में दृढ़ आस्तिक थीं। उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया व सेंट्रल लेप्रोसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की।

रेनुका

रेनुका एक आईसीएस अधिकारी सतीश चंद्र मुखर्जी की बेटी थीं उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई पूरी की। साल 1934 में, एआईडब्ल्यूसी के कानूनी सचिव के रूप में उन्होंने ह्यभारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगताह्न नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत कियो रेणुका ने एक समान व्यक्तिगत कानून कोड के लिए तर्क दिया और कहा कि भारतीय महिलाओं की स्थिति दुनिया में सबसे अन्यायपूर्ण में से एक थी। साल 1943 से साल 1946 तक वह केन्द्रीय विधान सभा, संविधान सभा और अनंतिम संसद की सदस्य थी। साल 1952 से 1957 में, उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में राहत और पुनर्वास के मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके साथ ही, वह साल 1957 में और फिर 1962 में वह लोकसभा में मालदा की सदस्य थे। उन्होंने अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद की स्थापना की।

सरोजिनी नायडू

सरोजिनी नायडू का जन्म हैदराबाद में 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली भारतीय महिला थीं और उन्हें भारतीय राज्य गवर्नर नियुक्त किया गया था। उन्हें लोकप्रिय रूप से ह्यनाइटिंगेल ऑफ इंडियाह्न भी कहा जाता है। उन्होंने किंग्स कॉलेज (लंदन) और बाद में कैम्ब्रिज के गिरटन कॉलेज में अध्ययन किया। साल 1924 में उन्होंने भारतीयों के हित में अफ्रीका की यात्रा की और उत्तरी अमेरिका का दौरा कियो भारत वापस आने के बाद उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ो सरोजिनी नायडू अपनी साहित्यिक शक्ति के लिए भी जानी जाती थी।

सुचेता कृपलानी

सुचेता का जन्म हरियाणा के अंबाला शहर में साल 1908 में हुआ थो उन्हें विशेषरूप से साल 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। कृपलानी ने साल 1940 में कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की भी स्थापना की। आजादी के बाद, कृपलानी के राजनीतिक कार्यकाल में नई दिल्ली के एक सांसद और फिर उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में वह श्रम, सामुदायिक विकास और उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत रही। वह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं।

विजया लक्ष्मी पंडित

विजया लक्ष्मी पंडित का जन्म 18 अगस्त 1900 में इलाहाबाद में हुआ था और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थीं। साल 1932 से 1933, साल 1940 और साल 1942 से 1943 तक अंग्रेजों ने उन्हें तीन अलग-अलग जेल में कैद किया था। राजनीति में विजया का लंबा करियर आधिकारिक तौर पर इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव के साथ शुरू हुआ। साल 1936 में, वह संयुक्त प्रांत की असेंबली के लिए चुनी गयी और साल 1937 में स्थानीय सरकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी ऐसा पहली बार था जब एक भारतीय महिला कैबिनेट मंत्री बनी।

एनी मास्कारेन

एनी मास्कारेन का जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम में एक लैटिन कैथोलिक परिवार में हुआ था। वह त्रावणकोर राज्य से कांग्रेस में शामिल होने वाली पहली महिलाओं में से एक थीं और त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्यकारिणी का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनीं। वह त्रावणकोर राज्य में स्वतंत्रता और भारतीय राष्ट्र के साथ एकीकरण के आंदोलनों के नेताओं में से एक थीं। अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए, उन्हें साल 1939 से साल 1977 से विभिन्न अवधि के लिए कैद किया गया था।

“लीला रॉय का जन्म अक्टूबर 1900 में असम के गोलपाड़ा में हुआ था। उनके पिता डिप्टी मजिस्ट्रेट थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते थे। उन्होंने साल 1921 में बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और सभी बंगाल महिला उत्पीड़न समिति की सहायक सचिव बनी और महिलाओं के अधिकारों की मांग के लिए मीटिंग की व्यवस्था की। साल 1923 में अपने दोस्तों के साथ उन्होंने दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना की जो राजनीतिक चर्चा के केंद्र बन गए।

सेना ही नहीं निजी जिंदगी में जिंदादिल थे सीडीएस बिपिन रावत

वाकई जनरल बिपिन रावत जैसा कोई न था और न है। देश ने एक ऐसा जांबाज योद्दा खो दिया। जिसकी हनक से दुश्मन देशों के पशीने छूट जाते थे। अपनी जांबाजी, वीरता, अदम्य साहस के लिए पहचाने जाने वाले जनरल बिपिन रावत के वो बयान आज भी लोगों के जेहन में है। जिसमें उन्होंने कहा था - चीन अपनी हद में रहे वरना नया भारत उसके घर में घूसकर मारने में रंचमात्र की भी देरी नहीं करेगी। जब हम जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल हैं। खास यह है कि वो मानवता के साथ-साथ समाजसेवा के क्षेत्र में भी कई मौकों पर अग्रणी भूमिका निभाई है। मतलब साफ है जनरल रावत केवल सेना में ही नहीं बल्कि निजी जिंदगी में भी बहादुर और जिंदादिल इंसान थे। वे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता का होना जरुरी मानते थे। उनका मानना था कि सरहद पर जवान देश की रक्षा करता है जबकि पत्रकार देश के भीतर रहते हुए लोकतंत्र की रक्षा करता है। सर्जिकल स्ट्राइक के चाणक्य थे बिपिन रावत, आतंकियों के लिए काल बना था उनका ये एक फैसला

सुरेश गांधी

जी हां, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन देश की खातिर लिए किए गए उनके अदम्य साहस व निर्णय को भुलाया जा नहीं जा सकता। वे देश के पहले चीफ डिफेंस स्टाफ बने थे और जीवन से बड़े व्यक्तित्व थे जो सेना को अपना परिवार मानते थे। 8 दिसम्बर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए एक हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए। हेलिकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई, जिसमें जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी शामिल थीं। इस अचानक हुए हादसे से पूरा देश स्तब्ध रह है। जनरल रावत ने सेना के विकास में हम भूमिका निभाई थी। उन्होंने समय-समय पर चीन और पाकिस्तान को लेकर सख्त बयान दिए थे जिसकी खूब चर्चा हुई थी। जनरल रावत पाकिस्तान के मुकाबले चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे। उन्होंने 13 नवंबर 2021 को ही कहा था कि भारत की सुरक्षा के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था, भारत की सुरक्षा में चीन सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले साल चीन से लगते सीमावर्ती इलाकों में लाखों जवानों और हथियारों की तैनाती की गई है। उनका जल्द बेस की तरफ लौटना मुश्किल है। भारत और चीन के बीच 13 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन आपसी भरोसे की कमी की वजह से सीमाविवाद सुलझ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के मामले में उन्होंने कहा था, पाकिस्तान के विरुद्ध हमारी सेना तैयार है। पाकिस्तान को हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ करने का प्रयास करने दें, और हमारे सशस्त्र बल बिल्कुल अलग तरह से उसकी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति है।

उनकी साहस को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत उस वक्त जीवित थे जब उन्हें हेलिकॉप्टर के मलबे से निकाला गया। उस दौरान वो अपना नाम बताने में सक्षम थे। एक वरिष्ठ प्रमुख फायरमैन और

बचावकर्मी की माने तो ये काफी जटिल ऑपरेशन था, क्रैश साइट पर कुछ लोगों के शरीर के निचले हिस्से बुरी तरह जल गये थे, बाद में रावत को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। वे पूरे होशोहवास में थे। हादसे के बाद क्रैश साइट पर पहुंचे लोगों को उन्होंने अपना नाम भी बताया था। जहां हादसा हुआ वो काटेरी गांव के पास का इलाका है।

कोटारी के पोथम पोन्नम ने चॉपर के क्रैश होने से पहले उसके गुजरने की आवाज सुनी थी। उन्होंने बताया कि इसके कुछ ही समय बाद एक जोरदार धमाका हुआ और पता चला कि हेलिकॉप्टर क्रैश हो चुका है। कटेरी के रहने वाले लोगों ने जिले के अधिकारियों को खबर दी थी जिसके बाद उनके इलाके की बिजली एहतियातन काट दी गई थी। जहां तक उनकी उपलब्धियों का सवाल है तो 1978 में सेना की 11वीं गोरखा राइफल्स की पांचवी बटालियन में कमीशन मिला। भारतीय सैन्य अकादमी में उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर मिला। 1986 में चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इंफैंट्री बटालियन के प्रमुख थे। उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स के एक सेक्टर और कश्मीर घाटी में 19 इन्फेन्ट्री डिवीजन की अगुआई भी की। कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का नेतृत्व भी किया। 1 सितंबर 2016 को उप सेना प्रमुख की जिम्मेदारी संभाली थी और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद बनाए जाने की घोषणा पीएम मोदी ने लाल किले पर दिए 15 अगस्त के भाषण से की थी। बिपिन रावत को यूआईएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एसएम, वीएसएम के साथ वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें दो मौके पर सीओएएस कमेंडेशन और आर्मी कमेंडेशन भी दिया जा चुका है।

> उनकी साहस को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत उस वक्त जीवित थे जब उन्हें हेलिकॉप्टर के मलबे से निकाला गया। उस दौरान वो अपना नाम बताने में सक्षम थे। एक वरिष्ठ प्रमुख फायरमैन और बचावकर्मी की माने तो ये काफी जटिल ऑपरेशन था, क्रैश साइट पर कुछ लोगों के शरीर के निचले हिस्से बुरी तरह जल गये थे।

चीन के सामने मजबूती खड़ा है भारत

अप्रैल 2021 में जनरल रावत ने रायसीना डायलॉग में भारत-चीन सीमा विवाद को लेकर कहा था कि चीन अपनी हर बात मनवाना चाहता है लेकिन भारत उसके सामने मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा था, चीन चाहता है माय वे ऑर नो वे। वो अपनी हर बात मनवाना चाहता है। भारत ने साबित किया है कि किसी भी तरह का दबाव डालकर उसे पीछे नहीं धकेला जा सकता है।

पीओके को लेकर चेताया था पाकिस्तान को

जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए पीओके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, जब हम जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल हैं। पीओके इसलिए अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है क्योंकि इस पर हमारे पड़ोसियों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। अवैध कब्जा वाले इलाके को पाकिस्तान नहीं, आतंकवादी नियंत्रित करते हैं। उन्होंने आगे कहा था, पीओके आतंकियों के द्वारा नियंत्रित है। पाकिस्तान आगे भी जम्मू-कश्मीर में छद्म युद्ध जारी रखेगा। वो पंजाब समेत देशके बाकी हिस्सों में भी समस्या पैदा करेगा जिसकी वो लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारी सेना उसे सफल नहीं होने देगी।सितंबर 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के एक हफ्ते बाद जनरल रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए पाकिस्तान-चीन को लेकर भारत को आगाह किया था। उन्होंने कहा था, भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ दो मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है।

माचिस की डिबिया के कारण हुआ था सेलेक्शन

मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले बिपिन रावत ने बचपन में ही भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देखा था। बिपिन रावत ने कहा था, यूपीएससी द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा को पास करने के बाद उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इस सेलेक्शन के लिए मैं इलाहाबाद गया था, जहां 4 से 5 दिनों की सख्त ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद फाइनल इंटरव्यू होना था. इंटरव्यू के लिए सभी कैंडिडेट एक कमरे के बाहर लाइन में खड़े थे और इस दौरान बिपिन रावत थोड़ा नर्वस हो गए थे, क्योंकि यही मौका था जो एनडीए में एंट्री दिला सकते थे या फिर बाहर कर सकते थे. बिपिन रावत ने बताया, इंटरव्यू हॉल में ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी मौजूद थे. उन्होंने मेरी हॉबी पूछी. मैं उन्हें बताया कि मुझे ट्रैकिंग का बहुत शौक है. उन्होंने पूछा कि यदि आपको ट्रैकिंग पर जाना हो और वो ट्रैकिंग 4-5 दिन की हो तो आप एक सबसे अहम सामान का नाम बताएं जो आप अपने पास रखना चाहेंगे? इस पर मैंने कहा था कि ऐसी स्थिति में में अपने पास माचिस रखूंगा. इस पर अधिकारी ने पूछा कि माचिस ही क्यों? तो बिपिन रावत ने कहा कि माचिस से मैं बहुत सारे काम कर सकता हूं? बिपिन रावत ने उनसे कहा था, जब आदिकाल में मनुष्य जंगलों में रहा करता था तो उसने सबसे पहले आग की खोज की थी, इसलिए मेरी नजर में मेरे लिए माचिस ही सबसे जरूरी है.

2015 में भी दुर्घटना के शिकार हुए थे जनरल रावत

साल 2015 में भी जनरल बिपिन रावत इसी तरह की एक दुर्घटना का शिकार हुए थे। उस समय वो नागालैंड में पोस्टेड थे और उनका हेलीकॉप्टर एक ऑपरेशन के दौरान क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम चीता है और ये भी काफी आधुनिक माना जाता है. इस हादसे के बाद काफी लोगों को लगा था कि जनरल बिपिन रावत इसमें सुरक्षित नहीं बचेंगे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ये खबर आई थी कि वो इस हादसे में बाल बाल बचे गए हैं.

कैंसर पीड़ितों की जान भी रावत की पत्नी

जनरल रावत की पत्नी का नाम मधुलिका था, जो आर्मी वाइफ्लस वेल्फेयर असोसिएशन की अध्यक्ष भी थीं। वह मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थीं और दिवंगत राजनेता मृगेंद्र सिंह की बेटी थीं। मधुलिका रावत ने अपनी शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में की। इसके अलावा वह कई तरह से सोशल वर्क के अलावा कैंसर पीड़ितों के लिए काम करती थीं। जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत दो बेटियों के पैरेंट्स थे. उनकी एक बेटी का नाम कृतिका रावत है. सार्वजनिक तौर पर बिपिन रावत की बेटियों के बारे में बेहद कम जानकारी है. लेकिन दोनों बेटियां जनरल बिपिन रावत की शान थीं. बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं और वे लेफ्टिनेंट-जनरल के पद तक पहुंचे. उनकी मां उत्तरकाशी से विधायक रहे किशन सिंह परमार की बेटी थीं.

करगिल युद्ध में दिखाया था शौर्य

63 साल के जीवन में जनरल रावत ने कई ऐसे काम किए, जो हमेशा याद रखे जाएंगे. उरी हमले के बाद सीमा पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक पैरा कमांडोज ने भले ही की थी लेकिन उसके पीछे दिमाग जनरल रावत का था. अशांत इलाकों में काम करने के अनुभव को देखते हुए मोदी सरकार ने दिसंबर 2016 में जनरल रावत को दो वरिष्ठ अफसरों पर तरजीह देते हुए आर्मी चीफ बनाया था. मणिपुर में जून 2015 में आतंकी हमले में कुल 18 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन एनएससीएन-के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था. तब 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे. जनरल रावत आर्मी चीफ से 31 दिसंबर 2019 को रिटायर होने के बाद देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे. उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले जनरल रावत को पूर्वी सेक्टर में कश्मीर घाटी और पूर्वोत्तर में काम करने का लंबा अनुभव था. करगिल के युद्ध में भी उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया था.

कामयाबी की सीढ़ियां

16 दिसंबर 1978 को जनरल बिपिन रावत बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट सेना में भर्ती हुए थे. 1980 में वो लेफ्टिनेंट के पद पर प्रमोट हुए. 1984 में उन्हें सेना ने कप्तान की रैंक दी. 1989 में वह मेजर बने. 1998 में वह लेफ्टिनेंट कर्नल थे. इसके बाद करगिल में युद्ध हुआ था. साल 2003 में वह कर्नल बनाए गए. 4 साल बाद साल 2007 में वरिष्ठता को देखते हुए उन्होंने ब्रिगेडियर बनाया गया. साल 2011 में वह मेजर जनरल बने. 2014 में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट हुए. 1 जनवरी 2017 को मोदी सरकार ने उन्हें आर्मी चीफ का पद दिया.

सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन का किया नेतृत्व

भारतीय सेना ने 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर कई आतंकी शिविरों को नष्ट कर दिया था. बड़ी बात ये है कि जनरल बिपिन रावत के उप सेना प्रमुख बनने के एक महीने के अंदर ही सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था. हमले में कई आतंकी भी मारे गए थे. उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले में कई जवानों के शहीद हो जाने के बाद सेना ने ये कार्रवाई की थी. जनरल रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने देश की सीमा के पार जाकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर कई आतंकियों को ढेर किया था. मणिपुर में जून 2015 में आतंकी हमले में कुल 18 जवान शहीद हो गए थे. इसके बाद 21 पैरा के कमांडो ने सीमा पार जाकर म्यांमार में आतंकी संगठन एनएससीएन-के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था. तब 21 पैरा थर्ड कॉर्प्स के अधीन थी, जिसके कमांडर बिपिन रावत ही थे.

फौजी है पूरा परिवार

बिपिन रावत मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले थे उनका जन्म पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था। रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हो चुके

“ जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख रहते हुए पीओके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। उन्होंने कहा था, जब हम जम्मू-कश्मीर की बात करते हैं, तो इसमें पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र भी शामिल हैं। पीओके इसलिए अवैध कब्जे वाला क्षेत्र है क्योंकि इस पर हमारे पड़ोसियों ने अवैध तरीके से कब्जा किया है। अवैध कब्जा वाले इलाके को पाकिस्तान नहीं, आतंकवादी नियंत्रित करते हैं।

हैं। वहीं उनकी मां प्रदेश के उत्तकांशी की रहने वाली हैं, जो पूर्व विधायक किशन सिंह परमार के बेटी भी हैं। बिपिन रावत, सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला, और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकसला के स्टूडेंट रह चुके हैं। दिसंबर 1978 में बिपिन रावत भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बाद रावत ने 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में कमान संभाली थी, फिर वह सीडीएस यानि तीनों सेनाओं के प्रमुख बने।

पिता से मिली देशभक्ति

रावत को भी देशभक्ति और बहादुरी विरासत में मिली थी. उन्होंने उरी, जम्मू और कश्मीर, सोपोर आदि जगहों पर सेना में मेजर, कर्नल और ब्रिगेडियर आदि पोस्ट पर सालों तक अपनी सेवा दी. 1 सितंबर 2016 को उन्होंने सेना में उप-प्रमुख बनाया गया. जिसके बाद सरकार ने देश का 27वां आर्मी चीफ बनाया.

मिले हैं कई सेना मेडल

सेना में रहने हुए सीडीएस बिपिन रावत को कई सारे मेडल से सम्मानित किया गया था, जिसमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल आदि शामिल हैं.

अपने पीछे छोड़ गए दो बेटियां

एक का नाम कीर्तिका और दूसरी बेटी का नाम तारिणी है। कीर्तिका की शादी हो चुकी है और वो मुंबई में रहती हैं। तारिणी दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। वे कीर्तिका से छोटी हैं। सार्वजनिक तौर पर बिपिन रावत की बेटियों के बारे में बेहद कम जानकारी है, लेकिन दोनों बेटियां जनरल बिपिन रावत की शान थीं।

हेलिकॉप्टर दुर्घटना की खबर के बाद से ही देशवासियों का मन भारी था। टीवी पर घटना से जुड़ी पलपल की खबरें सुन रहे थे। उम्मीद थी, बिपिन रावत सकुशल बच जाएंगे, कोई चमत्कार होगा, बुरी खबर सुनने को नहीं मिलेगी? पर, ढलती शाम के वक्त जैसे ही वायुसेना की ओर से सीडीएस बिपिन रावत के न रहने की खबर सार्वजनिक हुई, देश गमगीन हो गया, सभी स्तब्ध रह गए। थोड़ी देर तो किसी ने भी खबर पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस दुखद घटना का हमें सामना करना ही पड़ा। सबको एकीन हो गया कि देश ने एक सच्चा सिपाही खो दिया। बिपिन रावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिप्रिय सैन्य अधिकारियों में एक हुआ करते थे। उनकी काबिलियत पर उनको पहाड़ जैसा भरोसा था। रावत द्वारा सेना से संबंधित लिए निर्णयों पर वो आंख मूंद कर अपनी स्वीकृति दे दिया करते थे। यही कारण था कि उनके सेवानिवृत होने के बाद उनकी सेवाएं प्रधानमंत्री लेना चाहते थे, तभी सीडीएस का नया औहदा ईजाद किया गया जिस पर उन्हें बैठाया गया। रावत के निधन से देश को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई शायद ही हो पाए, उनकी कई योजनाएं धरी रह गई। चीन, पाकिस्तान जैसे खुरापाती पड़ोसी देशों से लड़ने की सैन्य रणनीतियां बना रहे थे, चीन की सेना को सबसे ज्यादा अगर डर था तो बिपिन रावत की चतुर रणनीतियों से था। लड़ने की प्लानिंग का उनका ब्लूप्रिंट अलहदा हुआ करता था। कश्मीर में पनपते नए किस्त के आतंकवाद की कमर अगर किसी ने तोडी. थी, तो वह रावत ही थे। विभिन्न सैन्य सेवाओं का उनके पास 43 वर्षों का बेजोड़ अनुभव था। जनरल रावत हिंदुस्तान के पहले और वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। रावत ने जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख का पदभार संभाला था। उनकी वीरता के संबंध में हम आज जितनी भी बातें कहें या सुनाए, कम हैं। उनकी अदम्य सैन्य वीरता के समक्ष शब्द कम पड़ रहे है। जुबान अपने आप रुक रही है।

रावत सीडीएस से पूर्व भारतीय थलसेना के प्रमुख भी रहे। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक इस पद की उन्होंने सोभा बढ़ाई। फिलहाल, हादसे की तत्कालिक जांच के आदेश दिए गए हैं, और देने भी चाहिए, फिर भी हादसा है या कोई सुनियोजित साजिश? हर पहलुओं पर रक्षा मंत्रालय की जांच समिति और तमिलनाडु सरकार की लोकल बॉडी जांच कर रही है। तमिलनाडु का कुन्नूर क्षेत्र जहां बुधवार दोपहर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस जगह को छावनी में तब्दील किया गया है। तमाम एजेंसियां अपने-अपने स्तर पर जांच सैंपल एकत्र कर रही हैं, ताकि घटना के मूल नतीजे तक पहुंचा जा सकें। हादसे में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका समेत अन्य 13 सेना के उच्चाधिकारियों के ना रहने की पुष्टि हुई है।

जबकि, हादसे में जिंदा बचे इकलौते सर्वाइवर रहे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं, ईश्वर उन्हें जल्द सेहतमंद करे और घटना की असल वजह बता सकें। इस दर्दनाक घटना से समूचा देश दुखी है, हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है। जिन-जिन से वह कभी मिले थे, वह जानते होंगे उनके भीतर एक हसौड़ इंसान भी जीता था। बड़े मजाकिया लहजे में सामने वाले को जबाव देते थे। उनके चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं होती थी। इसके पीछे की ताकत वह अपनी पत्नी को बताया करते थे। जो तकरीबन उनके साथ में ही रहती थीं। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, घटना के वक्त भी वह साथ थीं और एक साथ ही दोनों ने इस नश्वर दुनिया को अलविदा कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है।

बहरहाल, ये दुर्घटना साजिश भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे किस्से हैं जिन पर एकाएक शक होता है। कहीं वो कोई साजिश के शिकार तो नहीं हो गए? दरअसल, वह पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के लिए एक अलग युद्धक नीति में लगे थे। पाकिस्तान की प्रत्येक चाल का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। कश्मीर में उन्होंने आतंकवादियों को कठोरता के साथ कुचलने की नीति अपनाई हुई थी। इसके लिए उन्होंने सेना को खुली छूट दी हुई थी। वे बाहरी दुश्मनों के साथ-साथ आंतरिक दुश्मनों को भी खुलकर ललकार रहे थे। देशद्रोही ताकतों को भी कठोरता के साथ कुचलने की पैरवी करते थे। इसलिए अंदुरूनी स्तर पर भी उनके दुश्मनों की कमी नहीं थी। अवैध हथियार माफियाओं की उन्होंने कमर तोड़ी हुई थी। मौजूदा सरकार में हथियार दलालों की कतई नहीं चल रही थी। सेना के लिए जरूरी सामानों की आपूर्ति में चल रही रिश्वतखेरी भी उन्होंने रोकी हुई थी। इस कारण आपूर्ति दलाल उनसे खासे नाराज थे। जनरल बिपिन रावत जो उत्कृष्ट कार्य करके गए हैं, उन्हें आने वाली पीढ़ियां भी कभी भुला नहीं पाएंगी। हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में उनका बहुत योगदान स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण हुआ करती थी। ऐसे योद्धा को बारंबार प्रणाम।

रावत के निधन से देश को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई शायद ही हो पाए, उनकी कई योजनाएं धरी रह गई। चीन, पाकिस्तान जैसे खुरापाती पड़ोसी देशों से लड़ने की सैन्य रणनीतियां बना रहे थे, चीन की सेना को सबसे ज्यादा अगर डर था तो बिपिन रावत की चतुर रणनीतियों से था। लड़ने की प्लानिंग का उनका ब्लूप्रिंट अलहदा हुआ करता था। कश्मीर में पनपते नए किस्त के आतंकवाद की कमर अगर किसी ने तोडी. थी, तो वह रावत ही थे।

प्रदूषण में पराली जलाने का कोई बड़ा योगदान

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के उच्च स्तर में पराली जलाने का कोई बड़ा योगदान नहीं है। "एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार और दिल्ली में पीएम 2.5 और पीएम 10 सांद्रता में औसत क्षेत्रीय योगदान दिखाने के लिए सांकेतिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए" पीएम 2.5 और पीएम 10 में कृषि जलने का संबंधित योगदान सर्दियों में सिर्फ 4% और 7% था।

इस साल 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सात दिनों तक गंभीर (401-500) क्षेत्र में रहा है। इनमें से प्रत्येक दिन, दिल्ली के पीएम 2.5 योगदान में खेत की आग का योगदान 26% -48% के बीच था। ये आंकड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावे के विपरीत उड़ सकते हैं, जिससे लगता है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाना वास्तव में दिल्ली की खराब हवा के लिए समस्या नहीं थी। क्योंकि खेत की आग के योगदान पर सफर डेटा - यह एकमात्र सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा स्रोत है - केवल 20 अक्टूबर से उपलब्ध है, यह विश्लेषण लंबी अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है।

यह संभवतः पूरे वर्ष के लिए एक औसत संख्या है। अगर यही तर्क लागू किया जाए तो दिल्ली में प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या नहीं है। उसी हलफनामे से पता चलता है कि 2016 और 2020 के बीच, दिल्ली में "गंभीर" अदक दिनों की संख्या कभी भी 25 से अधिक नहीं थी। भले ही किसी को "बहुत खराब" अदक दिनों की संख्या (301 और 400 के बीच की रीडिंग) को जोड़ना हो। संख्या यह इस अवधि के दौरान 64 (2020) और 126 (2016) के बीच आती है। स्पष्ट रूप से, उच्च एक्यूआई वाले दिन उन दिनों की तुलना में एक बड़ी समस्या है जब एक्यूआई इतना खराब नहीं होता है। एक्यूआई स्तर अधिक होने पर खेत में आग का योगदान महत्वपूर्ण होता है।

एक्यूआई और पीएम 2.5 नंबरों के विपरीत, दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर

> “इस साल 20 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सात दिनों तक गंभीर (401-500) क्षेत्र में रहा है। इनमें से प्रत्येक दिन, दिल्ली के पीएम 2.5 योगदान में खेत की आग का योगदान 26% -48% के बीच था। ये आंकड़े केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावे के विपरीत उड़ सकते हैं, जिससे लगता है कि पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाना वास्तव में दिल्ली की खराब हवा के लिए समस्या नहीं थी।

पर खेत की आग के योगदान पर डेटा 20 अक्टूबर से पहले की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। 2012 से एक उच्च रिजॉल्यूशन पर दैनिक डेटा है जो पंजाब और हरियाणा में उपग्रहों से आग की संख्या पर देखा गया है। 2018 के बाद से दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर (2018 से पहले वायु गुणवत्ता स्टेशन बहुत कम थे) के साथ इस डेटा को पढ़ने से पता चलता है कि उस अवधि में व्यापक प्रतिध्वनि है जब शहर में खेत में आग और प्रदूषण का स्तर चरम पर था।

निश्चित रूप से, यह दिखाने के लिए शोध मौजूद हैं कि उन दिनों भी जब खेतों में आग लगी हो, दिल्ली के पीएम 2.5 के स्तर में उनका योगदान कम हो सकता है। हालांकि, यह दिल्ली के प्रदूषण स्तरों के लिए अनुकूल होने के कारण खेत की आग के सबूत की तुलना में अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण अधिक विचलन है। 2018 का एक लेख, उत्तर भारत के पराली उत्सर्जन का उद्देश्य मूल्यांकन और दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय जर्नल साइंस ऑफ द टोटल एनवायरनमेंट में प्रकाशित इस प्रश्न में एक उपयोगी अंतर्दृष्टि देता है।

"हालांकि उक्त अवधि (10 अक्टूबर -10 दिसंबर, 2018) के दौरान पराली जलाना एक नियमित प्रक्रिया थी, विभिन्न अग्नि गणनाओं के साथ, दिल्ली के पीएम 2.5 पर बायोमास जलने का प्रभाव प्रतिशत योगदान के साथ दिन-प्रतिदिन के आधार पर भिन्न होता है। पराली जलाने का प्रतिशत 1% से 58% तक है, क्योंकि यह वायु द्रव्यमान के परिवहन मार्ग पर अत्यधिक निर्भर है, जो हवा की दिशा और हवा की गति के नेतृत्व में क्षेत्र के मौसम संबंधी मापदंडों को लक्षित करने के लिए स्रोत द्वारा नियंत्रित होता है," हलफनामे में कहा गया है।

अखबार में कहा गया है, "दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर पराली जलाने का प्रभाव न केवल पंजाब और हरियाणा में जलाए गए बायोमास की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि घुसपैठ की ऊंचाई, हवा की दिशा और दिल्ली एयरशेड में हवा के रहने के समय पर उच्च हवा की गति के संयुक्त प्रभाव पर निर्भर करता है।"

इस तथ्य को देखते हुए कि कोई भी नीति हवा की गति और दिशा जैसे मौसम संबंधी कारकों को नियंत्रित नहीं कर सकती है, यह मौसम विज्ञान के मोर्चे पर एक दैवीय हस्तक्षेप की उम्मीद करने के बजाय खेत की आग को नियंत्रित करने के प्रयास करने के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें से कोई भी, निश्चित रूप से, यह कहना नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए अन्य कारक जिम्मेदार नहीं हैं, या अन्य कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है।

> “2012 से एक उच्च रिजॉल्यूशन पर दैनिक डेटा है जो पंजाब और हरियाणा में उपग्रहों से आग की संख्या पर देखा गया है। 2018 के बाद से दिल्ली में पीएम 2.5 के स्तर (2018 से पहले वायु गुणवत्ता स्टेशन बहुत कम थे) के साथ इस डेटा को पढ़ने से पता चलता है कि उस अवधि में व्यापक प्रतिध्वनि है जब शहर में खेत में आग और प्रदूषण का स्तर चरम पर था।

रूस के एस-400 मिसाइल से ताकतवर होगी भारतीय वायु सेना

एक रूसी अधिकारी ने रविवार को दुबई में कहा कि एस-400 वायु रक्षा प्रणाली, जिनमें से पांच को भारत ने 2018 में रूस से लगभग 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा था, की डिलीवरी शुरू हो गई है और यह निर्धारित समय के अनुसार चल रही है। पहली इकाई के साल के अंत तक चालू होने की उम्मीद है। अधिग्रहण में अमेरिका और भारत के बीच एक राजनयिक टूटने की संभावना है, जब दोनों देश एक कड़े रिश्ते की राह पर हैं। दुनिया में सबसे उन्नत और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है, एस-400 में ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहां तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने की क्षमता है। एक विशेष क्षेत्र पर एक ढाल के रूप में कार्य करने का इरादा रखने वाली ये मिसाइल प्रणाली लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली है। नाटो द्वारा नामित रअ-21 ग्रोलर, और रूस के अल्माज सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित, एस-400 घुसपैठ करने वाले विमान, मानव रहित हवाई वाहन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को शामिल कर सकता है, हाल ही में इंडो-पैसिफिक कमांड के लिए अमेरिकी वायु सेना के जर्नल में एक लेख में कहा गया है। यह "हवाई हमलों से सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संपत्तियों की रक्षा के लिए डिजाइन की गई एक एंटी-एक्सेस/एरिया इनकार (ए 2 / एडी) संपत्ति के रूप में सामने आया है"।

प्रत्येक इकाई में दो बैटरी होती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम, एक निगरानी रडार, और सगाई रडार और चार लंच ट्रक होते हैं।

रूस 1993 से एस-400 विकसित कर रहा है। परीक्षण 1999-2000 में शुरू हुआ और रूस ने इसे 2007 में तैनात किया।

वाशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज थिंक टैंक के अनुसार, इसके "मिशन सेट और क्षमताएं लगभग यूएस पैट्रियट सिस्टम के बराबर हैं" लेकिन कुछ पैट्रियट इंटरसेप्टर के विपरीत, "एस-400 मिसाइल रक्षा प्रौद्योगिकी वर्तमान में हिट-टू-किल बैलिस्टिक को नियोजित नहीं करता है।

यह प्रणाली चार प्रकार की मिसाइलों से सुसज्जित है: 40 किमी तक की छोटी दूरी; मध्यम-सीमा 120 किमी तक; लंबी दूरी की 48ठ6 250 किमी तक जा रही है, और बहुत लंबी दूरी की 40ठ6ए 400 किमी तक और 180 किमी की उड़ान ऊंचाई तक। एक अध्ययन के अनुसार, यह एक साथ 600 किमी की सीमा में 160 वस्तुओं को ट्रैक कर सकता है, और 400 किमी की सीमा में 72 वस्तुओं को लक्षित कर सकता है।

यह कैसे काम करता है?

एस-400 एक हवाई खतरे का पता लगाता है जो वायु रक्षा बुलबुले (जिस क्षेत्र को इसकी रक्षा करनी है) के पास पहुंच रहा है, खतरे के प्रक्षेपवक्र की गणना करता है, और इसका मुकाबला करने के लिए मिसाइलों को दागता है।

इसमें लंबी दूरी के सर्विलांस राडार होते हैं जो कमांड व्हीकल को सूचना भेजते हैं। लक्ष्य की पहचान करने पर, कमांड वाहन मिसाइल लॉन्च का आदेश देता है। आयरन डोम के बारे में सोचें, जिसे हाल ही में इजराइल द्वारा गाजा मई से आने वाले रॉकेटों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। केवल, एस-400 में बहुत बड़े क्षेत्र को उन खतरों से बचाने की क्षमता है जो बहुत दूर हैं।

भारत ने उन्हें क्यों खरीदा है?

मिसाइलों, या चीन या पाकिस्तान से लड़ाकू विमानों के हमलों से बचाने के लिए थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की फरवरी में एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारतीय वायु सेना के दृष्टिकोण से, "क्षमता या लागत के दृष्टिकोण से, इसकी लंबी दूरी की वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम कोई वैकल्पिक प्रणाली नहीं है।

रिपोर्ट में अमेरिकी एमआईएम-104 पैट्रियट सिस्टम के साथ एस-400 की तुलना की गई है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "मुख्य रूप से शुद्ध एंटी-एयरक्राफ्ट भूमिका पर कम ध्यान के साथ मिसाइल रक्षा की ओर उन्मुख है"। इसने कहा कि पैट्रियट के लिए 25 मिनट की तुलना में एस-400 को पांच मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। 1.38 किमी/सेकंड की तुलना में इसकी गति 4.8 किमी/सेकंड है। पैट्रियट के 1 बिलियन की तुलना में लगभग $ 500 मिलियन की प्रति बैटरी लागत के साथ यह सस्ता भी है।

उन्हें कब तक पहुंचाया जाएगा?

दुबई में, सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिए रूस की संघीय सेवा के निदेशक दिमित्री शुगेव ने कहा: "रूस ने भारत को एस -400 वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति शुरू कर दी है, और पहला डिवीजन 2021 के अंत तक वितरित किया जाएगा"। भारत को वर्ष के अंत तक खरीदी गई पांच इकाइयों में से पहला प्राप्त होने की उम्मीद है। भारत ने अक्टूबर 2018 में पांच इकाइयों के लिए ऑर्डर दिया है। शुरूआत में, डिलीवरी 24 महीने के भीतर शुरू होनी थी, लेकिन कई कारणों से इसमें देरी

> पिछले 30 वर्षों के दौरान मुख्यतः 5 क्षेत्रों में विशेष कार्य हुआ था। देश में राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयास लगातार लगभग सभी केंद्र सरकारों द्वारा किए गए हैं परंतु इस कार्य में भी वर्ष 2014 के बाद से गति आई है। वित्तीय वर्ष 1991 में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का, 8 प्रतिशत की राशि तक पहुंच गया था। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5 प्रतिशत से नीचे ले आया गया था।

हुई है। सरकार ने जुलाई 2019 में संसद को बताया, जब भारत ने रूस को पहली किश्त के रूप में लगभग $800 मिलियन का भुगतान किया, कि सभी इकाइयों की अंतिम डिलीवरी अप्रैल 2023 तक होने की संभावना है।

यह सब किसके पास है?

कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। बेलारूस ने 2007 में इसका अनुरोध किया और 2016 में पहली डिलीवरी मिली। अल्जीरिया ने इसे 2014 में खरीदा और 2015 में पहली इकाई मिली। तुर्की ने दिसंबर 2017 में रूस के साथ एक ऑर्डर दिया था और जुलाई 2019 में डिलीवरी शुरू हुई। मिस्र, सऊदी अरब और कतर ने रुचि भी दिखाई है। भारत को चिंता इस बात की है कि चीन ने मार्च 2014 में ऑर्डर दिया और 2018 में डिलीवरी शुरू हुई। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के दौरान, जो मई 2020 में शुरू हुआ और अनसुलझा रहा, चीन ने कथित तौर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपने एस -400 को तैनात किया था।

अमेरिका इससे क्यों खफा है?

कई कारण हैं। एक यह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी रक्षा प्रणालियों पर अपनी पारंपरिक निर्भरता को खत्म कर दे। रूस दशकों से भारत के लिए सबसे बड़ा रक्षा भागीदार रहा है, एक ऐसा रिश्ता जो भारत के राजनयिक और रणनीतिक रूप से अमेरिका के करीब आने के साथ बदल रहा है; अमेरिका से आयात बढ़ा है, मुख्यतः रूसी आयात की कीमत पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च में जारी अंतरराष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण के रुझानों पर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-15 और 2016-20 के बीच भारत द्वारा हथियारों के आयात में 33% की कमी आई है, रूस 2011 में भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा। "हालांकि, दो अवधियों के बीच रूस की डिलीवरी में 53 प्रतिशत की गिरावट आई और कुल भारतीय हथियारों के आयात में इसकी हिस्सेदारी 70 से 49 प्रतिशत तक गिर गई।

2011-15 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता था, लेकिन 2016-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत के हथियारों का आयात पिछले पांच साल की अवधि की तुलना में 46 प्रतिशत कम था, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया।" रिपोर्ट में कहा गया है।

लेकिन भारत-अमेरिकी संबंधों के सौदे के बारे में चिंताओं का बड़ा कारण अमेरिका द्वारा पारित 2017 के कानून में निहित है, जिसका नाम काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट (सीएएटीएसए) है, जिसका उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से अमेरिकी विरोधियों ईरान, रूस और उत्तर कोरिया का मुकाबला करना है। अधिनियम का शीर्षक कक्रअपने रक्षा उद्योग सहित रूसी हितों में प्रतिबंधों से संबंधित है। अधिनियम अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी रक्षा और खुफिया क्षेत्रों के साथ "महत्वपूर्ण लेनदेन" में संलग्न व्यक्तियों पर धारा 235 में उल्लिखित 12 सूचीबद्ध प्रतिबंधों में से कम से कम पांच लगाने का अधिकार देता है। अमेरिका ने लंबे समय से नाटो के सहयोगी रहे तुर्की पर दिसंबर 2020 में सिस्टम की खरीद को लेकर प्रतिबंध लगाए थे।

जनवरी में, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि अगर भारत एस-400 प्रणाली की खरीद के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे प्रतिबंध लग सकते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उअअळरअ के तहत "रूसी निर्मित एस-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए भारत का बहु-अरब डॉलर का सौदा भारत पर अमेरिकी प्रतिबंधों को ट्रिगर कर सकता है"।

कुछ दिनों बाद, भारत में निवर्तमान अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच "अंतरसंचालन" के मुद्दों को उठाया, जिसे एस-400 सौदे के परोक्ष संदर्भ के रूप में देखा गया था।

भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि "भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है" और "भारत की रूस के साथ एक विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है"। मंत्रालय ने कहा, "भारत ने हमेशा एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है। यह हमारे रक्षा अधिग्रहण और आपूर्ति पर भी लागू होता है जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों द्वारा निर्देशित होते हैं।"

हालांकि यह मसला अनसुलझा है। दो अमेरिकी सीनेटरों ने कथित तौर पर पिछले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखा था, जिसमें उनके प्रशासन से खरीद पर भारत के खिलाफ किसी भी प्रतिबंध को माफ करने का आग्रह किया गया था।

अब जब डिलीवरी शुरू हो गई है, तो यह देखा जाना बाकी है कि अमेरिका क्या कार्रवाई करने को तैयार है, खासकर जब उसने चीन के उदय का मुकाबला करने के लिए इंडो-पैसिफिक को अपना मुख्य क्षेत्र बनाया है।

> “ भारत में अभी तक हालांकि कृषि क्षेत्र एवं सोशल क्षेत्र (स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र एवं पीने का जल, आदि क्षेत्रों सहित) में सुधार कार्यक्रम लगभग नहीं के बराबर लागू किए गए थे इसलिए देश में आज भी लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहते हुए हुए अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है एवं गरीबी में अपना जीवन जीने को मजबूर है। दरअसल, इन कारणों से देश में आर्थिक असमानता की दर में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है।

क्या तेलों के घटती कीमतों का युग खत्म हो गया?

उपभोक्ताओं को ईंधन की बढ़ती कीमतों से राहत मिल रही है क्योंकि तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने दिवाली की पूर्व संध्या पर राज्य सरकारों द्वारा शुल्क में संशोधन के बाद पेट्रोल और डीजल की पंप कीमतों को अपरिवर्तित रखा है। तदनुसार, तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले दैनिक मूल्य संशोधन तंत्र के तहत, पेट्रोल और डीजल की कीमतें शुक्रवार को लगातार 15 वें दिन स्थिर रहीं। दिल्ली में पेट्रोल का पंप भाव 6 बजे गिरकर 103.97 रुपये प्रति लीटर हो गया। 4 नवंबर को पिछले दिन के 110.04 रुपये प्रति लीटर से समान स्तर पर बना हुआ है। डीजल की कीमतें भी राजधानी में 86.67 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर है।

कोलकाता में भी कीमतें स्थिर रहीं, जहां नवंबर के पहले सप्ताह में पेट्रोल की कीमत 5.82 रुपये घटकर 104.67 रुपये प्रति लीटर और डीजल 11.77 रुपये घटकर 89.79 रुपये प्रति लीटर हो गई। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत भी 101.40

“दिल्ली में पेट्रोल का पंप भाव 6 बजे गिरकर 103.97 रुपये प्रति लीटर हो गया। 4 नवंबर को पिछले दिन के 110.04 रुपये प्रति लीटर से समान स्तर पर बना हुआ है। डीजल की कीमतें भी राजधानी में 86.67 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहीं। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल 94.14 रुपये प्रति लीटर है।

रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.43 रुपये प्रति लीटर पर बनी हुई है। देश भर में भी, ईंधन की दरें काफी हद तक अपरिवर्तित रहीं लेकिन स्थानीय करों के स्तर के आधार पर खुदरा दरें भिन्न थीं। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें जो पिछले एक महीने में कई मौकों पर 85 डॉलर प्रति बैरल के तीन साल के उच्च स्तर को छू चुकी हैं, अब नरम होकर 82 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं। यूएस इन्वेंट्री में वृद्धि ने कच्चे तेल की कीमतों को नीचे धकेल दिया है, लेकिन ओपेक + का निर्णय दिसंबर में उत्पादन में केवल क्रमिक वृद्धि पर ही इसे और बढ़ा सकता है। इससे तेल कंपनियों पर फिर से ईंधन की कीमतों में संशोधन करने का दबाव पड़ सकता है। कीमतों में कटौती और ठहराव से पहले, पिछले 56 दिनों में से 30 दिनों में डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 9.90 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमतें भी पिछले 52 दिनों में 28 दिनों में बढ़ी हैं, जिससे पंप की कीमत 8.85 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। 1 जनवरी से, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुल्क में कटौती से पहले 26 रुपये प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। 3 नवंबर को केंद्र द्वारा उत्पाद शुल्क में कटौती कोविड महामारी की शुरूआत के बाद से इस तरह की पहली कवायद थी। दरअसल, कोविड राहत उपायों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए सरकार ने पिछले साल मार्च और फिर मई में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तेजी से संशोधन किया था। मार्च 2020 और मई 2020 के बीच पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये और 16 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया था और केंद्र द्वारा शुल्क में कटौती का फैसला करने से पहले डीजल पर 31.8 रुपये और पेट्रोल पर 32.9 रुपये प्रति लीटर था।

“कीमतों में कटौती और ठहराव से पहले, पिछले 56 दिनों में से 30 दिनों में डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत 9.90 रुपये प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमतें भी पिछले 52 दिनों में 28 दिनों में बढ़ी हैं, जिससे पंप की कीमत 8.85 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई है। 1 जनवरी से, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में शुल्क में कटौती से पहले 26 रुपये प्रति लीटर से अधिक की वृद्धि हुई है।

मेष गुरु की कृपा से भाग्य की बृद्धि होगी।कर्म स्थान का शनि मेहनत के बाद ही सफलता देगा।शनिबार की संध्या में लड्डू गरीबों में बांटे।सेहत का ध्यान रखें। भगवान श्री सूर्यनारायण को अर्ध्य प्रदान करें। शुभ अंक 1 और शुभ रंग लाल है।

बृषभ मन खिन्न रहेगा। बहुत मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। जीवन में आनंद का वातावरण बनाने के लिए दुर्गासप्तशती का पाठ करें।विद्यार्थी के लिए और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल अवसर हैं। शुभ अंक 2 और शुभ रंग सफेद या ऑफ वाइट।

मिथुन स्वास्थ्य का ध्यान रखें।प्रतिष्ठा तो मिलेगी। लेकिन धनागमन में थोड़ी परेशानी होगी।अष्टम शनि के लिए चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें।दशम सूर्य आपके जीवन में विशेष कृपा बनाएगा।मा के महालक्ष्मी रूप की पूजा करें। शुभ अंक 3 रंग हरा और लाल।

कर्क सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।घर के स्त्री पक्ष का सेहत चिंता का कारण बनेगा।प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अनुकूल समय है।हनुमान जी की आराधना करें।बजरंगबाण का पाठ करें। शुभ अंक 7। शुभ रंग- गुलाबी

सिंह मत्र के वेश में छुपे शत्रु से सावधानी की जरूरत है।श्री लुक्ष्मी नारायण की पूजा से धन लाभ होगा।संध्या प्रहर घी का चतुर्मुख दीपक अपने घर के मुख्यद्वार पर प्रतिदिन जलाए। उत्सव और मांगलिक कार्य की बातें करने का उपयुक्त समय है। शुभ रंग नीला। शुभ अंक 8।

कन्या पंचम शनि करियर के क्षेत्र में अच्छे अवसर देंगे। विद्या व बुद्धि से सफलता प्राप्त होंगे।गुरु के प्रभाव से लीवर या पेट की समस्या रहेगी। महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्रवण करें। शुभ रंग पीला। शुभ अंक 3।

बृश्चिक आपके आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन आगमन का योग है। भाई के लिए समय अनुकूल नही है।बाएं सुर बाले पीले गणपति का तस्बीर घर में रखें।प्रतिष्ठा व सम्मान का योग है। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 5।

तुला भाग्य का राहु राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे।गुरु की कृपा से शत्रु व रोग का नाश होगा।शनि माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नही है।चांदी के पात्र से गाय का कच्चा दूध नदी में बहाएं।अनुकूलता बनी रहेगी। शुभ रंग लाल। शुभ अंक 4।

मकर जिद्द छोड़ना होगा।बाएं हाथ की कलाई में पीला धागा बांधने सेनुक्सान कम होगा।राहु अचानक व विचित्र परिणाम दे सकता है।कालभैरव जी की पूजा करें। शुभ रंग सफेद। शुभ अंक 7।

कुम्भ झूठ से नफरत होगी। झूठे लोगों से सामना होगा।लाभ होंगे लेकिन मन के अनुकूल नही।लेकिन मान सम्मान बढेगा।मंगल कार्य के लिए आगे बढ़े।आवश्यकता को कम करें।चोट चपेट से बचना होगा।हल्दी का गांठ अपने पर्स में रखें।ॐ नमो नारायणाय का जाप करें। शुभ रंग-गुलाबी। शुभ अंक 8।

धनु धन का आगमन होगा।लेकिन सूर्यास्त के बाद दूध व दही का सेवन नही करें।आत्मभिमान से बचना होगा।अहंकार को हावी नही होने दे।हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक 6। शुभ रंग हरा।

मीन सूर्य की कृपा से पद व प्रतिष्ठा की बृद्धि होगी।गुस्सा पर नियंत्रण रखें।दुश्मन से सचेत जरूरी है।नजर बचना होगा।घर की शांति राहु के कारण नियंत्रण में नही रहेगा। सफेद कपड़े में सिंधा नामक घर के मुख्य द्वार पर बांधे। शुभ रंग -हरा। शुभ अंक 9।

DENTAL PROBLEM MOSTLY HAVE GENETIC ORIGIN

Dr. Shivali Singh

In recent times, Every one wants to have a amiable pleasant appearance be it a boy, girl or elder people . Common man is getting more aware of his looks now a days and dentition is a very important aspect . Everyone wants to look good and dentistry has come a long way .In the current scenario due to overuse of chemicals and pesticides we are unable to get proper diet and most people encounter pyrrohoea i.e. gingivitis and Swollen gums. It is corrected by oral prophylaxis , scaling and intake of Vitamin C tablets. Crooked teeth can be re-aligned by putting braces which come in vibrant colours .A beautiful dame can be made out of an ugly duckling. Oral cavity's well being is directly related to alimentry canal. Having pyrrhoea or periodontal disease can even cause heart disease and constipation can cause ulcers in month. So it is imperative that we take care of our overall health which includes half yearly dental check ups .I have seen that dental problem mostly have genetic origin as well as the environmental factors but there is nothing to worry about. There are advanced ways to tackle all the problems . Earlier people without any teeth had to make do with heavy dentures but now flexible dentures which fit easily in the mouth are made .Also implants are inserted in the edentulous ridge of the patient and fixed dentures are fabricated which look very good esthetically also and pose no problem or discomfort to the wearer. Discolored teeth can be covered with beautiful glass ceramic crowns and bridges which function in accordance with natural teeth .Also Jaw -corrective surgeries are done to enhance the looks of a person who wants a certain facial profile .If a person has pain in temporo mandibular joint , relief is given by injecting saline solution .Over the counter teeth whitening kits are available where a person can change and match the shade of his teeth according to his need.Intra oral xrays and RVGS have made dental practice very easy and affordable now a days and you can even put diamond glitters on your teeth.These are the happiest times of Dentistry and hopefully more advancement happens in future..

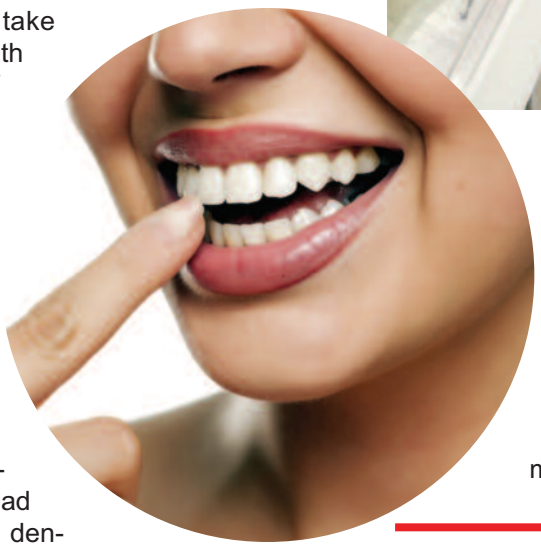

“Everyone wants to look good and dentistry has come a long way .In the current scenario due to overuse of chemicals and pesticides we are unable to get proper diet and most people encounter pyrrohoea i.e. gingivitis and Swollen gums. It is corrected by oral prophylaxis , scaling and intake of Vitamin C tablets.

परिणीति ने बॉलीवुड में पूरे किए 10 साल, कहा-अभी तो सफर शुरू हुआ है

परिणीति चोपड़ा ने 10 साल पहले फिल्म 'लेडीज वर्सेज रिकी बहल' से डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने 'इश्कजादे', 'शुद्ध देसी रोमांस' और 'हंसी तो फंसी', 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' और 'संदीप और पिंकी फरार' जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। सिनेमा में अपने 10वें वर्ष पर, अभिनेत्री का कहना है कि वह अब अपने करियर में कभी भी कंफर्ट जोन के साथ काम नहीं करेंगी। परिणीति ने कहा कि मुझे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐतिहासिक फिल्मों में काम करने और हमारे शानदार फिल्म उद्योग के कुछ बेहतरीन निर्देशकों, अभिनेताओं, तकनीशियनों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो समय बहुत जल्द निकल जाता है और यह मेरे साथ हुआ है।

"सिनेमा में 10 साल पूरे करने के बाद, मुझे लगता है कि मैंने अभी अपनी यात्रा शुरू की है। मैं सिनेमा में अपने अगले दशक के लिए वास्तव में जाने के लिए उत्सुक हूं। मुझे उस तरह के प्रस्ताव पसंद आ रहे हैं जो मुझे मिल रहे हैं।"

परिणीति ने कहा कि मुझे भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐतिहासिक फिल्मों में काम करने और हमारे शानदार फिल्म उद्योग के कुछ बेहतरीन निर्देशकों, अभिनेताओं, तकनीशियनों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। जब आप अपने काम से प्यार करते हैं, तो समय बहुत जल्द निकल जाता है और यह मेरे साथ हुआ है। "सिनेमा में 10 साल पूरे करने के बाद, मुझे लगता है कि मैंने अभी अपनी यात्रा शुरू की है। मैं सिनेमा में अपने अगले दशक के लिए वास्तव में जाने के लिए उत्सुक हूं। मुझे उस तरह के प्रस्ताव पसंद आ रहे हैं जो मुझे मिल रहे हैं।"

अभिनेत्री ने जोर देकर कहा कि 'द गर्ल ऑन द ट्रेन' और 'संदीप और पिंकी फरार' के साथ, निर्देशक उन्हें एक नई रोशनी की तरह देख रहे हैं और मुझे उस तरह का काम दे रहे हैं जो मैं हमेशा से करना चाहती थी।

परिणीति अगली बार मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ 'ऊंचाई' और रणबीर कपूर के साथ 'एनिमल' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी।

अभियंता प्रशान्त बंधे परिणय सूत्र में

अभियंता प्रशान्त कुमार सिन्हा 19 नवम्बर (शुक्रवार) को पटना के होटल चाणक्या में दिल्ली निवासी सुरभि सिन्हा के साथ परिणय सूत्र में बंधे। प्रशान्त सिन्हा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सेवा निवृत, जद्यू कलमजीवी प्रकोष्ठ के पूर्व महासचिव तथा जीकेसी (ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस) के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार सिन्हा के पुत्र हैं। सिन्हा मूलतः पटना जिला के ग्राम जैवर के निवासी हैं।

प्रशान्त सिन्हा बंगलुरु (बंगलोर) स्थित आई टी कम्पनी में कम्प्यूटर साइंस इंजीनियर है। इनका का शुभ विवाह नई दिल्ली स्थित नेल्सन कम्पनी से सेवानिवृत्त प्रबन्धक विजय कुमार सिन्हा की पुत्री सुरभि सिन्हा के सम्पन्न हुआ है। सुरभि सिन्हा बी एच यू से माइक्रोबायलॉजी में एम ए सी की है और दिल्ली स्थित निजी कम्पनी में सप्लायर चेन में कार्यरत है।

FORD HOSPITAL, PATNA

A NABH Certified Multi Super-Speciality Hospital

PATNA

A 105-Bedded Hospital Run by Three Eminent Doctors of Bihar

उत्कृष्ठ एवं अपनत्व की अनुभूति

Dr. Santosh Kr.

Dr. B. B. Bharti

Dr. Arun Kumar

PATIENT SAFETY & QUALITY OF CARE
NABH
PRE ACCREDITED

Best Promising Multi Speciality Hospital 2018 Bihar.

हृदय रोग चिकित्सा के लिए बेहतरीन टीम

2nd Multi Speciality NABH Certified Hospital of Bihar

फोर्ड हॉस्पीटल में उपलब्ध सेवाएं

क्लीनिकल सर्विसेस

- कार्डियोलॉजी
- क्रिटीकल केयर
- न्यूरोलॉजी
- स्पाईन सर्जरी
- नेफ्रोलॉजी एवं डायलेसिस
- ऑर्थोपेडिक एवं ट्रॉमा
- ओब्स एवं गॉबनेकोलौजी
- पेडिएट्रिक्स
- पेडिएट्रिक सर्जरी
- साइचिरेट्री एवं साइकोलॉजी
- रेस्पिरेट्री मेडिसिन
- यूरोलॉजी
- सर्जिकल ऑन्कोलौजी

Empaneelled with CGHS, ECR, CISF, NTPS, Airport Authority, Power Grid & other Leading PSUs, Bank, Corp. & TPS

New Bypass (NH-30) Khemnichak, Ramkrishna Nagar, Patna- 27
Helpline ; 9304851985, 9102698977, 9386392845, Ph.: 9798215884/85/86
E-mail : fordhospital@gmail.com web. : www.fordhospital.org